Indian Council
of World Affairs

SAPRU HOUSE PAPER

नई वास्तविकताओं का पता लगाना

अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

अन्वेषा घोष

Indian Council
of World Affairs

SAPRU HOUSE PAPER

नई वास्तविकताओं का पता लगाना

अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

अन्वेषा घोष

Indian Council
of World Affairs

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य सृजित करना तथा विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और चिंतन के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद् वर्तमान में आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान का संचालन करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करता है तथा अनेक प्रकाशन प्रकाशित करता है। इसके पास एक समृद्ध पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, तथा यह 'इंडिया क्वार्टरली' नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

नई वास्तविकताओं का पता लगाना
अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन
पहली बार प्रकाशित, सितंबर 2024
© भारतीय वैश्विक परिषद

ISBN:978

93-83445-87-5

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। कॉपीराइट मालिक की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग या अन्यथा, पुनरुत्पादित, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में प्रकाशित तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेखकों की अपनी है और उनकी व्याख्या अनिवार्य रूप से भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

भारतीय वैश्विक परिषद् सप्रू
हाउस, बाराखंभा रोड नई
दिल्ली 110001, भारत:
+91-11-2331 7246 | F: +91-11-2332
0638

www.icwa.in

विषय-सूची

सार संक्षेप 5

परिचय 7

नई सीमा का पता लगाना : तालिबान के पुनरुत्थान के बाद से अफ़गानिस्तान के पड़ोसी संबंध 8

पाकिस्तान 11

ईरान 20

मध्य एशियाई पड़ोसी 32

चीन 46

भारत 53

क्षेत्र पर तालिबान का जोर 59

अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के लिए आगे की राह? 65

तालिबान द्वारा सरकार विरोधी आतंकवादी समूहों को दिया जा रहा कथित समर्थन 65

वाइर पर विवाद 68

सीमा असुरक्षा 71

शरणार्थी प्रवाह 73

आईएसकेपी से बढ़ता खतरा 76

अफ़गानिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी 82

निष्कर्ष 85

लेखक के बारे में 93

अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

सार-संक्षेप

दो दशकों के विद्रोह के बाद, तालिबान ने 15 अगस्त, 2021 को विजेता होकर काबुल में प्रवेश किया और अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तालिबान का आक्रमण ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने, समूह के साथ 2020 के शान्ति समझौते में निर्धारित किए गए अनुसार, अफगानिस्तान से अपने शेष सैनिकों को वापस बुला लिया है । तालिबान के सत्ता में वापस आने से अफगानिस्तान के पड़ोसियों में तालिबान की अफगानिस्तान पर प्रभावी रूप से शासन करने की क्षमता तथा पड़ोसी देशों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता और संदेह पैदा हो गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, तालिबान ने स्वयं को एक विद्रोही समूह से एक कार्यात्मक प्रशासन के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। इसके बाद, अफगानिस्तान के निकटतम पड़ोसी देशों, अर्थात् ईरान, पाकिस्तान, चीन, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने भी अफगानिस्तान की नई वास्तविकताओं के साथ समायोजन करने का प्रयास किया है। यह सप्रू हाउस पेपर अगस्त 2021 में तालिबान के कब्ज़े के बाद से अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों का एक

व्यापक अवलोकन प्रदान करने का प्रयास करता है। इस पेपर की शुरुआत पड़ोसी राज्यों में तालिबान द्वारा कब्जे पर हुई तत्काल प्रतिक्रिया पर चर्चा से होती है और उसके बाद उन कुछ प्रमुख चिंताओं और हितों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने सात निकटतम पड़ोसी देशों में से प्रत्येक के तालिबान शासन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आकार दिया है। इसके बाद यह पेपर सत्ता में आने के बाद से क्षेत्र पर शासन के दबाव पर नजर डालता है। इसके बाद, हाल के वर्षों में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों की बदलती रूपरेखा को प्रभावित करने वाले मुद्दों के आधार पर, इस दस्तावेज में छह मुद्दों की पहचान की गई है, अर्थात्:

(i) अफगानिस्तान के पड़ोसियों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों को तालिबान का कथित समर्थन (जिन्हें सामूहिक रूप से सरकार विरोधी आतंकवादी समूहों के रूप में पहचाना गया है); (ii) जल विवाद; (iii) सीमा असुरक्षा, (iv) शरणार्थी आंदोलन;

(v) आईएसकेपी का बढ़ता खतरा; (vi) अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी। इस पेपर में विशिष्ट रूपरेखाओं का सामूहिक रूप से उपयोग करते हुए उन पर चर्चा की गई है, तथा तर्क दिया गया है कि ऊपर उल्लिखित कारक आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द: *अफ़गानिस्तान, तालिबान, निकट पड़ोसी, आतंकवाद, सुरक्षा को खतरा, जल-विवाद, शरणार्थी, नशीली पदार्थों की तस्करी, सीमा असुरक्षा।.*

अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

परिचय

15 अगस्त, 2021 को, दो दशक के विद्रोह का अंत चिह्नित करते हुए, तालिबान की काबुल में विजयी वापसी के मद्देनजर अफगानिस्तान ने अपने अशांत इतिहास में एक नए अध्याय में प्रवेश किया। यह त्वरित अधिग्रहण तालिबान के साथ 2020 के शांति समझौते के बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ हुआ। जैसे-जैसे यह समूह एक विद्रोही बल से एक शासकीय निकाय में परिवर्तित हुआ, अफगानिस्तान के पड़ोसियों के बीच युद्धग्रस्त राष्ट्र पर प्रभावी शासन करने की समूह की क्षमता के बारे में चिंताएं और संदेह बढ़ने लगे। इस निर्णायक क्षण ने ईरान, पाकिस्तान, चीन, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित पड़ोसी देशों को नव-तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। अगस्त 2021 के बाद की अवधि में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी विचारों का एक जटिल अंतर्संबंध देखा गया, क्योंकि इन देशों ने तालिबान के पुनरुत्थान के जवाब में अपनी नीतियों को पुनर्गठित किया। इस पृष्ठभूमि में, सप्रू हाउस पेपर का उद्देश्य अगस्त 2021 के बाद के युग में अफगानिस्तान के सात निकटतम पड़ोसियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को रेखांकित करना है। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि तालिबान शासन के साथ सहभागिता और पहुँच, आर्थिक

सहयोग और संबंधों के क्रमिक सामान्यीकरण के प्रश्न पर इन देशों की प्रतिक्रियाएँ किस प्रकार विकसित हुई हैं। इसमें कुछ प्रमुख चिंताओं और हितों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने तालिबान शासित अफगानिस्तान के अपने प्रत्येक पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है। इसके बाद यह आलेख सत्ता में आने के बाद से क्षेत्र पर शासन के दबाव पर विचार करता है। इसके बाद, हाल के वर्षों में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों की बदलती रूपरेखा को प्रभावित करने वाले मुद्दों के आधार पर, इस दस्तावेज में छह मुद्दों की पहचान की गई है,

अर्थात: (i) अफगानिस्तान के पड़ोसियों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों को तालिबान का कथित समर्थन (जिन्हें सामूहिक रूप से सरकार विरोधी आतंकवादी समूहों के रूप में पहचाना जाता है); (ii) जल विवाद; (iii) सीमा असुरक्षा; (iv) शरणार्थियों का प्रवाह (अफगानिस्तान के अंदर और बाहर दोनों ओर से); (v) इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत (आईएसकेपी) का बढ़ता खतरा; (vi) अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी। इस पेपर में विशिष्ट रूपरेखाओं का सामूहिक रूप से उपयोग करते हुए उन पर चर्चा की गई है, तथा तर्क दिया गया है कि उल्लिखित कारक आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच संबंधों की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि, यह शोध यह दावा नहीं करता है कि उल्लिखित मुद्दे तालिबान शासित अफ़गानिस्तान के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाले एकमात्र कारक हैं; इसमें उल्लिखित कारकों पर 15 अगस्त, 2021 और 31 दिसंबर, 2023 (अध्ययन की समयरेखा) के बीच उनकी आवर्ती प्रकृति और भविष्य में क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के आधार के कारण ध्यान केंद्रित किया गया है।

नई सीमा का पता लगाना : तालिबान के पुनरुत्थान के बाद से अफ़गानिस्तान के पड़ोसी संबंध

20 वर्ष से भी अधिक समय पहले, अफगानिस्तान की सीमा

से लगे छह देशों ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें देश के पुनर्निर्माण में मदद करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता और तत्कालीन तालिबान सरकार के पतन के बाद 'क्षेत्र में शांति और स्थिरता' की इच्छा व्यक्त की गई थी। वर्तमान में अफगानिस्तान की स्थिति उन छह देशों - चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान - द्वारा 2002 में की गई कल्पना से बहुत अलग है। अगस्त 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी सेनाओं की अचानक वापसी और तालिबान की सत्ता में वापसी ने कई नई सुरक्षा और विकास चुनौतियों को जन्म दिया है।

1 "Kabul Declaration on Good Neighbourly Relations". UNSC, December 24, 2002. Available at: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_021222_AfghanistanGoodNeighbourlyRelationsDeclaration_0.pdf

जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सरकारें अफगानिस्तान से आगे बढ़कर अन्य वैश्विक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगीं, अफगानिस्तान के सात निकटतम पड़ोसियों, अर्थात् पाकिस्तान, ईरान, चीन, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पास तालिबान के अधीन अफगानिस्तान की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को स्वीकार करने और अपने-अपने तरीके से उनका समाधान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

अफगानिस्तान में अब एक दर्जन से अधिक अंतरराष्ट्रीय उग्रवादी और आतंकवादी समूह मौजूद हैं। लिंग, जातीयता और धर्म के आधार पर भेदभाव व्यापक है, तथा मानवाधिकारों का हनन भी व्यापक है। पहले से ही कठिन मानवीय, विकासात्मक और आर्थिक स्थितियाँ और भी अधिक बिगड़कर एक ऐसे संकट में बदल गई हैं, जिसके समाप्त होने की संभावना नहीं है, जब तक कि तालिबान प्रशासन - जो कूटनीतिक रूप से अलग-थलग है और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन है - अधिक समावेशी सरकार बनाने, महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और आतंकवादी समूहों से निपटने की माँगों को पूरा करने में अड़ियल बना रहता है।

जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की

सरकारें अफगानिस्तान से आगे बढ़ गईं और अपना ध्यान अन्य वैश्विक मुद्दों की ओर मोड़ने लगीं, अफगानिस्तान के सात निकटतम पड़ोसियों, अर्थात् पाकिस्तान, ईरान, चीन, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान (मानचित्र 1 देखें) के पास तालिबान के अधीन अफगानिस्तान की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को स्वीकार करने और अपने तरीके से उनका समाधान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

तालिबान शासन के चार वर्षों के बाद, इनमें से कई देशों ने अफगानिस्तान की नई वास्तविकताओं को स्वीकार करने का प्रयास किया है तथा तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता दिए बिना उसके साथ जुड़ने के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया है।

सप्रू
हाउ
स
पेपर

Map 1. Afghanistan and its Neighbours

Source: google maps (https://www.google.com/maps/@35.8983022,64.9123935,5z?entry=ttu)

इनमें से कई पड़ोसी देशों ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने से पहले ही उसके साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया था, और इसलिए, विभिन्न देशों की राजधानियों में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने पर प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रही हैं। हालाँकि, तालिबान शासन के चार वर्षों के बाद, इनमें से कई देशों ने अफगानिस्तान की नई वास्तविकताओं को स्वीकार करने की कोशिश की है और तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता दिए बिना उसके साथ जुड़ने के लिए एक तंत्र विकसित करने की कोशिश की है। निम्नलिखित खंड में यह बताया गया है कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों ने तालिबान के कब्जे पर

किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसके बाद तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ प्रत्येक देश के संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

	फगानिस्तान
पाकि	पर तालिबान
स्ता	के कब्जे से
न	पहले,
अ	पाकिस्तान ने
ग	वर्षों तक
स्त	समूह का
	समर्थन किया
2	था, उसे
0	संसाधन और
2	सुरक्षित
1	आश्रय दोनों
	प्रदान किए
में	थे। तालिबान
	की वापसी
अ	को

पाकिस्तान की रणनीतिक जीत के रूप में देखा गया। अफगानिस्तान में तालिबान के उदय को शुरू में पाकिस्तान सरकार और रणनीतिकारों ने सकारात्मक रूप से देखा था, तथा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी खुले तौर पर इसका समर्थन किया था। लगभग दो दशकों के बाद काबुल में एक मैत्रीपूर्ण

सरकार स्थापित करने में कामयाब होने के बाद, तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान ने एक उत्साहपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अफगानों ने 'गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी हैं'।[2] जैसा कि स्पष्ट है, अफगानिस्तान में तालिबान के उदय को पाकिस्तान ने सकारात्मक दृष्टि से देखा था, और दोनों के बीच दशक पुराने संबंधों के

का
र
ण
,
य
ह
मा
ना
ग
या
था
कि
अ
फ
गा
न
तालिबान
अफगानिस्तान
में इस्लामाबाद
के हितों की
रक्षा करेगा।
इसलिए, यह
आश्चर्य की
बात नहीं थी
जब अक्टूबर
2021 में
काबुल में
सरकार को
आधिकारिक
रूप से
मान्यता दिए
बिना ही
पाकिस्तानी
अधिकारियों
ने अफगान
दूतावास और
वाणिज्य
दूतावासों को
तालिबान को

सौंप दिया।[3] कुछ ही दिनों के भीतर काबुल में तत्कालीन इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की उपस्थिति[4], जो कथित तौर पर तालिबान को उग्रवाद से शासन की ओर स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए थी, ने इस विश्वास को और अधिक बल प्रदान

कि

या

कि

अ

फ

गा

नि

स्ता

न

के

न

ए

शा

स

क

इ

स्ला

माबाद के भारी प्रभाव में थे। 'अंतरिम' कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क (जो पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए एक मूल्यवान परिसंपत्ति साबित हुआ है) का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व इस विचार को और पुष्ट करता है।

2 "Afghans have broken 'shackles of slavery': Pakistan PM Imran Khan". The Hindu, August 16, 2021. Available at:

shackles-of-slavery-pak-pm-imran-khan/article35939794.ece

3 "Taliban Install Diplomats in Pakistan Embassy, Missions" VOA, October 29, 2021. Available at: https://www.voanews.com/a/taliban-install-diplomats-in-pakistan-embassy-missions-/6289591.html

4 'Everything will be Okay': ISI chief during visit to Afghanistan". The Times of India, September 5, 2021. Available at: https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/everything-will-be-okay-isi-chief-during-visit-to-

https://www.thehindu.com/news/international/afghans-have-broken-

सप्रू हाउस पेपर

परि

चय 11

इस्लामाबाद तालिबान की 'अंतरिम' सरकार के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी मान्यता के साथ-साथ तत्काल वित्तीय सहायता के लिए पैरवी की। हालाँकि, अगले कुछ महीनों में, पाकिस्तान में आतंकवाद के फिर से उभरने, जो मुख्य रूप से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पुनरुत्थान के कारण हुआ, साथ ही बलूच विद्रोह और इस्लामिक स्टेट खुरासान की धमकियों ने तालिबान के संबंध में पाकिस्तान के शुरुआती उत्साह को कम कर दिया है। दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को निर्धारित करने वाले अन्य मुद्दों में डूरंड रेखा पर झड़पें और पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने का मुद्दा शामिल था।

1. डूरंड रेखा का सीमांकन

2,670 किलोमीटर लम्बी डूरंड रेखा का नाम ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 12 नवंबर 1893 को तत्कालीन अफगान शासक अमीर अब्दुर रहमान के साथ ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद, उत्तरोत्तर अफगान सरकारों ने तर्क दिया कि रेखा की वैधता 1993 में समाप्त हो गई, क्योंकि समझौते की वैधता 100 वर्षों के लिए थी। डूरंड रेखा न केवल दोनों देशों

को विभाजित करती है बल्कि पश्तून जनजातीय क्षेत्रों से भी होकर गुजरती है। पाकिस्तान में, पंजाबी और पश्तून डूरंड रेखा के साथ दो प्रमुख जातीय समूह हैं। पाकिस्तान में पश्तूनों की आबादी लगभग 15 प्रतिशत है। अफगानिस्तान में पश्तून सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो देश की आबादी का लगभग 42 प्रतिशत है।[5]

5 "Afghanistan and Pakistan Ethnic Groups. An ethnolinguistic map of showing different language and cultural groups across Afghanistan and Pakistan." National Geographic, August 2022. Available at: https://education.nationalgeographic.org/resource/afghanistan-and-pakistan-ethnic-groups (Accessed on 28.11.22)

जबकि पाकिस्तान ने डूरंड रेखा को अपनी पश्चिमी सीमा के रूप में मान्यता दी है, लेकिन किसी भी अफगान सरकार (1996 और 2001 के बीच तालिबान शासन सहित) ने डूरंड रेखा को पाकिस्तान के साथ वैध सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में विवादित सीमा पर बाड़ और सीमा चौकियां स्थापित करने के पाकिस्तान के प्रयासों को अफगानिस्तान की ओर से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। 2021 के अंत में, ऐसी रिपोर्टें और वीडियो प्रसारित किए गए, जिनमें तालिबान बलों को डूरंड रेखा के साथ पूर्वी नंगरहार प्रांत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा लगाए गए कंटीले तारों को उखाड़ते हुए दिखाया गया।[6] इस साल की शुरुआत में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थीं, जब तालिबान लड़ाकों को निमरोज प्रांत में सीमा पर बाड़ और पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट करते देखा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में 'कुछ जटिलता' के होने को स्वीकार किया था।[7] तालिबान के कब्जे के बाद से, डूरंड रेखा के पार तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़पों की कई घटनाएँ हुई हैं, खासकर देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में । सीमा पार हाल में हुई झडपों की वृद्धि के जवाब में, काबुल और इस्लामाबाद ने

स्थिति का आकलन करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है।[8] कथित तौर पर, काबुल ने **15** जनजातीय बुजुर्गों की एक समिति नियुक्त की है ताकि दोनों पक्षों के बीच

6 "Taliban tear down barbed wire fence put up by Pak forces as Durand Line border tension brews." WION, December 22, 2021. Available at: https://www.wionews.com/south-asia/taliban-tear-down-barbed-wire-fence-put-up-by-pak-forces-as-durand-line-border-tension-brews-438954 (Accessed on 28.11.22)

7 "After Taliban removed fencing from Pak-Afghan border, FM Qureshi admits there are 'complications'Read more." ANI News Agency, January 3, 2022. Available at: https://www.aninews.in/news/world/asia/after-taliban-removed-fencing-from-pak-afghan-border-fm-qureshi-admits-there-are-complications20220103182813/ (Accessed on 28.11.22)

8 "Pakistan-Afghanistan relations on boil? Fresh border clashes erupt along Durand Line." Times Now, November 22, 2022. Available at: https://www.timesnownews.com/world/pakistan-afghanistan-relations-on-boil-border-clashes-reported-along-durand-line-article-95681376 (Accessed on 26.11.22)

मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके।9 अफगान समाचार मीडिया ने बताया कि जनजातीय बुजुर्ग बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जनजातीय बुजुर्ग के हवाले से कहा कि यदि वार्ता विफल हो जाती है तो सभी जनजातियाँ अफगानिस्तान के साथ खड़ी होंगी। 10

2. *अफगान तालिबान ने पशिउन इस्लामी आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को समर्थन दिया।*

टीटीपी ने 2007 से पाकिस्तान में कई घातक हमले किये हैं। 2014 में पेशावर सैन्य स्कूल पर हमले के बाद, पाकिस्तानी सेना ने देश में टीटीपी के सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसके कारण कई टीटीपी सदस्यों को पड़ोसी अफगानिस्तान भागने पर मजबूर होना पड़ा। अफगान तालिबान की तरह टीटीपी भी मुख्यतः पश्तून समूह है। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि तालिबान का टीटीपी की कार्रवाइयों पर कितना प्रभाव है, लेकिन काबुल में सत्ता पर कब्जा करने के बाद उन्होंने अफगान जेलों से कई टीटीपी नेताओं को रिहा कर दिया और माना जाता है कि टीटीपी नेतृत्व ने अफगानिस्तान में शरण ले ली है।11 हाल

के वर्षों में टीटीपी हमलों में वृद्धि पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। पिछले कई वर्षों से इस्लामाबाद का कहना है कि अफगानिस्तान में विदेशी ताकतों की

मौजूदगी ने टीटीपी विद्रोह को बढ़ावा दिया है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद उम्मीद थी कि यह सशस्त्र समूह टीटीपी लड़ाकों पर लगाम लगाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। टीटीपी ने पाकिस्तान में जिहादी हिंसा में तेज़ी से इज़ाफ़ा किया।

9 "Afghani families displaced after Taliban, Pakistani military clash along Durand Line." ANI News, November 23, 2022. Available at: https://www.aninews.in/news/world/asia/afghani-families-displaced-after-taliban-pakistani-military-clash-along-durand-line20221123230936/ (Accessed on 26.11.22)

10 "Paktia families displaced by clashes with Pakistan." The Tolo News, November 22, 2022. Available at: https://tolonews.com/science-technology-180867 (Accessed on 25.11.22)

11 "Taliban release TTP's Maulvi Faqir Mohammad, other terrorists from Afghanistan prisons." India Today, August 18, 2021. Available at: https://www.indiatoday.in/world/story/taliban-maulvi-faqir-mohammad-terrorists-afghanistan-prisons-kabul-1842162-2021-08-18 (Accessed on 07.12.22)

14 नई वास्तविकताओं का पता लगाना अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

2021 में 294 हमले हुए - जो 2020 से 56 प्रतिशत की वृद्धि है और इनमें से 45 हमले अकेले दिसंबर में हुए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत, दोनों अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की 2,600 किलोमीटर (1,600 मील) से अधिक की सीमा पर स्थित हैं, अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से लगभग दैनिक हमले हुए हैं, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी सुरक्षा बल और नागरिक मारे गए हैं।[12] उनके कम से कम दो हमलों में चीनी कर्मचारियों और पाकिस्तान में चीनी राजदूत को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी चीन बेहद चिंतित हो गया।[13] अधिकांश मामलों में, ऐसी घटनाओं के कारण पाकिस्तान द्वारा प्रमुख सीमा चौकियों को बंद कर दिया गया, ताकि चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान पर दबाव डाला जा सके, जो समुद्र तक पहुँच न होने के कारण पाकिस्तान पर बहुत अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, तोरखम - एक प्रमुख उत्तर-पश्चिमी सीमा चौकी, उन चौकियों में से एक है, जिसे कई बार बंद किया गया है, मुख्यतः सुरक्षा बलों के बीच विभिन्न कारणों से झड़पों के बाद, जिनमें पाकिस्तान द्वारा सीमा बाड़ की मरम्मत भी शामिल है।[14] हालाँकि, ऐसी प्रतिक्रिया ज्यादा देर टिकी नहीं रह सकी और अधिकतर मामलों में इसे कुछ दिनों के लिए पुनः खोलना पड़ा।

12 Daud Khattak, " Taliban Takeover In Afghanistan Bolsters Pakistan's Insurgency."Gandhara.org, January 13, 2014. Available at: Taliban Takeover In Afghanistan Bolsters Pakistan's Insurgency (rferl.org) (Accessed on 1.12.22)

13 "China Is Unnerved by Increasing Attacks on Chinese in Pakistan". The Diplomat, September 28, 2021. Available at: https://thediplomat.com/2022/09/china-is-unnerved-by-increasing-attacks-on-chinese-in-pakistan/ (Accessed on 1.12.22)

14 "Trade resumes as Pak and Afghanistan reopen Torkham border after 10 days", Business Standard, January 25, 2024. Available at: https://www.business-standard.com/world-news/trade-resumes-as-pak-and-afghanistan-reopen-torkham-border-after-10-days-124012300285_1.html

सप्रू
हाउस
पेपर

अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद उम्मीद थी कि यह सशस्त्र समूह टीटीपी लड़ाकों पर लगाम लगाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। टीटीपी ने पाकिस्तान में जिहादी हिंसा में तेज़ी से वृद्धि की।

शुरुआत में, चीजें कुछ हद तक आशावादी लग रही थीं जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच तीन महीने के युद्धविराम समझौते की सुविधा दी और 4 जून, 2022 को एक समझौता किया, जहां उन्होंने वार्ता जारी रखने के लिए युद्धविराम को अनिश्चित काल तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।[15] हालाँकि, नवंबर 2022 में, टीटीपी ने जून में सरकार के साथ सहमत संघर्ष विराम की समाप्ति की घोषणा की और अपने लड़ाकों को देश भर में हमले करने के आदेश जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में हिंसा बढ़ गई। तालिबान के कब्जे के बाद से, पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 73 प्रतिशत[16] की वृद्धि देखी गई है, जिसमें जनवरी 2023 में पेशावर पुलिस मस्जिद[17] पर हुआ विनाशकारी हमला भी शामिल है, जिसमें 300 से

अधिक लोग हताहत हुए थे। अक्टूबर 2023 में, अफगान तालिबान ने एक फतवा या इस्लामी फरमान जारी किया, जिसमें उसके लड़ाकों को पाकिस्तान का विशेष उल्लेख किए बिना अफगानिस्तान के बाहर हिंसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह फतवा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर लक्षित था।[18] 2023 में, टीटीपी

की बढ़ती हिंसा के बीच, इस्लामाबाद से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के सामने आने वाले सुरक्षा खतरे पर चर्चा करने के लिए काबुल

15 "Afghan Taliban mediate Ceasefire between Pakistan and Pakistani Taliban". Indian Council of WorldAffairs, June 13, 2022. Available at: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=7474&lid=5011

16 "Did Pakistan Really Benefit From the Taliban Takeover in Afghanistan?" The Diplomat, August 15, 2023, Available at: https://thediplomat.com/2023/08/did-pakistan-really-benefit-from-the-taliban-takeover-in-afghanistan/

17 "Dozens killed in Pakistan mosque blast". Al Jazeera, January 30, 2023. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2023/1/30/peshawar-pakistan-mosque-explosion-casualties

18 "The Azadi Briefing: Afghan Taliban Bans Fighters From Waging 'Jihad' In Pakistan". RadioFreeEurope, October 27, 2023. Available at: https://www.rferl.org/a/azadi-briefing-afghan-taliban-pakistan-jihad-indonesia-refugees/32656456.html

16 नई वास्तविकताओं का पता लगाना अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

का दौरा किया, लेकिन यह प्रयास वांछित परिणाम देने में विफल रहा। अप्रैल 2022[19] और मार्च 2024[20] में पाकिस्तान ने तालिबान की ओर से प्रतिक्रिया में कमी के कारण अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से अफगान तालिबान को एक पक्ष लेने की चेतावनी दी है - या तो वे अफगान क्षेत्र के अंदर टीटीपी से निपटें, उन्हें निष्कासित करें, या गलत विकल्प चुनने के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यह स्पष्ट था कि अफगान तालिबान के साथ इस्लामाबाद का धैर्य खत्म हो रहा था, जब पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवर उल-हक काकर ने घोषणा की कि तालिबान नेतृत्व टीटीपी के पाकिस्तान विरोधी विद्रोह का समर्थन कर रहा था, जिसने पाकिस्तान में हिंसा में बड़ी वृद्धि में योगदान दिया था, जिसके कारण अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से 2,867 पाकिस्तानी मारे गए थे।[21] बाद में, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष दूत, आसिफ दुर्रानी ने काकर की तालिबान की आलोचना को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 'अफगानिस्तान में शांति वास्तव में पाकिस्तान के लिए एक दुःस्वप्न बन गई है'.[22] जबकि पाकिस्तान ने तालिबान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाया है, तालिबान ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद उसकी आंतरिक समस्या है और टीटीपी से निपटने

की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है।

3. अफगान नागरिकों का पाकिस्तान से निष्कासन

2 अक्टूबर, 2023 को पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने एक कठोर निर्णय लिया कि 1.7 मिलियन अफ़गानों सहित सभी 'अवैध अप्रवासियों' को निर्वासित कर दिया जाएगा यदि 1 नवंबर तक वे स्वेच्छा से बाहर नहीं निकलते हैं।[23]

19 "At least 47 dead in Afghanistan after Pakistan attacks: Officials." Al Jazeera, April 17, 2022. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2022/4/17/afghanistan-death-toll-in-pakistan-strikes-rises-to-47-official

20 "'Cousins at war': Pakistan-Afghan ties strained after cross-border attacks". Al Jazeera, March 19, 2024. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2024/3/19/cousins-at-war-pakistan-afghan-ties-strained-after-cross-border-attacks

21 "Pakistan to Taliban-Ruled Afghanistan: Choose Bilateral Ties or Support for Militants."VOA, Nov 8, 2023. Available at: https://www.voanews.com/a/pakistan-to-taliban-ruled-afghanistan-choose-bilateral-ties-or-support-for-militants-/7346720.html

22 "Pakistan accuses Afghan Taliban of controlling TTP." The Tribune, November 12, 2023, Available at: https://tribune.com.pk/story/2446070/pakistan-accuses-afghan-taliban-of-controlling-ttp

पाकिस्तान द्वारा अफगान शरणार्थियों को निष्कासित करने से उन मुद्दों की सूची में और इजाफा हो गया, जिसने काबुल के साथ इस्लामाबाद के संबंधों को और खराब कर दिया।

1980 के दशक के प्रारम्भ से ही अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें निर्वासित करने के लिए 7-8 बड़े प्रयास किए गए हैं; हालाँकि, काबुल और इस्लामाबाद के बीच कुछ समझौता विकसित होने के बाद ये प्रयास विफल हो गए। हालांकि, हाल के वर्षों में पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के साथ व्यवहार में काफी गिरावट आई है, क्योंकि देश के भीतर सुरक्षा विफलताओं के लिए उन्हें लगातार दोषी ठहराया जाता रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, आदेश जारी होने के बाद से 130,000 से अधिक अफगानी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जिससे क्रॉसिंग पॉइंट्स के दोनों ओर अवरोध पैदा हो गए हैं।**24** अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा कि 23 सितंबर से 22 अक्टूबर, 2023 के बीच लगभग 60,000 अफगान वापस लौटे और इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उत्तरी तोरखम सीमा और बलूचिस्तान प्रांत में चमन क्रॉसिंग के रास्ते वापस लौटे, जहां अधिकांश अफगान शरणार्थी रहते हैं।25 तालिबान शरणार्थी मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में वापस लौटने वालों की दैनिक संख्या सामान्य से तीन गुना अधिक है। तालिबान शरणार्थी मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में प्रतिदिन वापस लौटने वालों की संख्या

सामान्य से तीन गुना अधिक है।[26] 31 अक्टूबर को जारी एक बयान में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि वह अफगानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना उन्हें जबरन निर्वासित न करे।[27] पाकिस्तानी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर निर्वासन से पहले

"Pakistan orders illegal immigrants, including 1.73 mln Afghans, to leave." Reuters, October 3, 2023. Available at: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-orders-all-illegal-immigrants- leave-after-suicide-bombings-2023-10-03/ (Accessed on 31. 10.23)

23 "Taliban urges Pakistan to grant more time for undocumented Afghans to leave." Al Jazeera, November 2, 2023. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2023/11/1/taliban-urges-pakistan-to-grant-more-time-for-undocumented-afghans-to-leave (Accessed on 2. 11.23)

24 Afghans return to Taliban rule as Pakistan moves to expel 1.7 million, Reuters, Op.cit.

25 Ibid

26 Ibid

अफगानिस्तान में, वापस लौटने वाले अफगानियों की
आमद ने पहले से ही सीमित संसाधनों पर
दबाव बढ़ा दिया है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र पर
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और तालिबान के कब्जे के बाद
विदेशी सहायता में कटौती के कारण और भी अधिक दबाव में है।

लाखों अनिर्दिष्ट अफगानों की प्रक्रिया के लिए देश भर में कई केंद्र खोलने का फैसला किया है।[28] संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने कहा कि पाकिस्तान की योजनाएं महिलाओं और लड़कियों के लिए 'गंभीर सुरक्षा जोखिम' पैदा करती हैं जिन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है.[29]

अफगानिस्तान में, वापस लौटने वाले अफगानियों की आमद ने पहले से ही सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ा दिया है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और तालिबान के कब्जे के बाद विदेशी सहायता में कटौती के कारण और भी अधिक दबाव में है। अफ़गान शरणार्थी मंत्रालय ने कहा कि वह वापस लौटने वालों को पंजीकृत करने और फिर उन्हें अस्थायी शिविरों में रखने का इरादा रखता है। पाकिस्तान से वापस आने वाले नए शरणार्थियों के प्रबंधन के लिए नंगरहार प्रांत के लालापुर जिले में एक शिविर स्थापित किया गया है।[30] तालिबान प्रशासन ने कहा कि वह वापस लौटने वालों के लिए नौकरियां ढूंढने का प्रयास करेगा। हालाँकि, तालिबान के सत्ता में आने के बाद से

बेरोजगारी दर दोगुनी से भी अधिक हो गई है, इसलिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तालिबान प्रशासन को वापस लौटने वालों के पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त सहायता और मानवीय सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन बदलती वैश्विक व्यवस्था के मद्देनजर पश्चिमी दुनिया की घटती रुचि के कारण अफगानिस्तान को विदेशी सहायता मिलना और भी मुश्किल हो सकता है।

"Pakistan to open holding centres ahead of Afghan deportations."Duetsche Welle, November 1, 2023. Available at: https://www.france24.com/en/live-news/20231031-pakistan-to-open-holding-centres- ahead-of-afghan-deportations

28 Afghans return to Taliban rule as Pakistan moves to expel 1.7 million, Reuters, Op.cit.

29 "Taliban slams Pakistan's riot order on refugees, calls expulsion 'inhumane, unfair and barbaric'", India Narrative, October 5, 2023. Available at: https://www.indianarrative.com/world-news/taliban-slams-pakistans-riot-order-on-refugees-calls-expulsion-inhumane-unfair-and-barbaric-152739.html

काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद इस्लामाबाद को अफ़गान तालिबान से तीन विशेष अपेक्षाएँ थीं: (क) टीटीपी को सौंपना; (ख) डूरंड रेखा के प्रति सम्मान बनाए रखना; और (ग) अफगानिस्तान से भारत के प्रभाव को हटाने के लिए कदम उठाना। सत्ता में आए तीन साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की कोई भी उम्मीद पूरी नहीं की है, और इस कारण पाकिस्तानी प्रतिष्ठान में निराशा है।

दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में जटिलता की डिग्री को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष सैयद असीम मुनीर द्वारा जनवरी 2024 में दिए गए एक बयान से समझा जा सकता है, जहाँ उन्होंने कहा: 'एक अकेले पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है'।31 अफगान तालिबान ने मुनीर की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पहले कहा था कि पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी विफलता और अपनी धरती पर सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता के लिए अफगानिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए। काबुल पर कब्जा करने के बाद इस्लामाबाद को अफगान तालिबान से तीन विशिष्ट अपेक्षाएँ थीं: (क) टीटीपी को सौंपना; (ख) डूरंड रेखा के प्रति सम्मान बनाए रखना; और (ग) अफगानिस्तान से भारत के प्रभाव को हटाने के लिए कदम उठाना। सत्ता

में आए तीन साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की किसी भी उम्मीद को पूरा नहीं किया है, और इस प्रकार पाकिस्तानी प्रतिष्ठान में निराशा (जैसा कि उपर्युक्त बयानों से स्पष्ट है) होना स्वाभाविक है।

ईरान

ईरान ने अफगानिस्तान से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी को वस्तुतः तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण के रूप में देखा। इस प्रकार, जब अगस्त 2021 में काबुल तालिबान के हाथों में चला गया, तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने सावधानीपूर्वक

30 "Pakistan's Munir Accuses Afghanistan of Supporting Balochistan Insurgents" Tolo News, January 26, 2024. Available at: https://tolonews.com/afghanistan-187130

तैयार किए गए शब्दों का उपयोग करते हुए अफगानिस्तान में नई वास्तविकता का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया।[32] उन्होंने संकेत दिया कि अफगानिस्तान के प्रति ईरान की नीति पारस्परिक होगी, जो क्षेत्र में अपने हितों और प्राथमिकताओं के प्रति तालिबान द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता से प्रभावित होगी। हालांकि इससे दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई, लेकिन इससे तेहरान की तालिबान पर पूरी तरह भरोसा करने की अनिच्छा का संकेत मिलता है। फिर भी, ईरान उन मुट्ठी भर देशों में से एक था, जिन्होंने तालिबान के कब्जे के बाद भी काबुल में अपने दूतावास चालू रखे। प्रारंभ में, ईरान ने काबुल में अफगान दूतावास को उस शासन को सौंपने का विरोध किया, जिसे वह मान्यता नहीं देता, तथा सभी समुदायों के प्रतिनिधियों वाली एक समावेशी सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालाँकि, फरवरी 2023 तक, ऐसी रिपोर्टें आईं कि तेहरान उन बहुत कम लेकिन महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो गया था, जिन्होंने तालिबान राजनयिकों को ईरान में अफगानिस्तान के दूतावास का प्रभार संभालने की अनुमति दी थी।[33] ईरान ने अमेरिका के बाद के उभरते परिदृश्य को अपने पड़ोसी के लिए शांति और स्थिरता लाने के अवसर के रूप में देखा।[34] तालिबान को अफगानिस्तान की वास्तविकता का हिस्सा मानते हुए,[35] ईरान ने अधिक व्यावहारिक भागीदारी नीति अपनानी शुरू कर दी है, जबकि उसने स्वयंभू 'अफगानिस्तान

इस्लामिक अमीरात' को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।

पिछले कुछ वर्षों में, तेहरान सार्वजनिक रूप से तालिबान, जो कि एक पूर्व कट्टर दुश्मन था, के साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

32 Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei's statement in Platform X after the Taliban takeover of Afghanistan. @Khamenei.Ir, August 28, 2021. Available at: https://twitter.com/khamenei_ir/status/1431554721844797442

33 "Iran to handover Afghan Embassy in Tehran to Taliban" ANI, February 24, 2023. Available At: https://www.aninews.in/news/world/asia/iran-to-handover-afghan-embassy-in-tehran-to-taliban20230224224118/

34 "Iran Says U.S. "Failure" in Afghanistan a Chance for Durable Peace," Reuters, August 16, 2021, https://www. reuters.com/world/middle-east/iran-says-us-failure-afghanistan-chance-durable-peace-2021-08-16/

35 "Foreign Ministry Spokesperson: The Taliban are Part of the Reality of Afghanistan," Entekhab, February 1, 2021, https://www.entekhab.ir/002Vwu

चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो, ईरान हमेशा अफगानिस्तान को लेकर चिंतित रहा है, लेकिन बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और तनावपूर्ण आंतरिक वातावरण ने तेहरान को तालिबान के साथ बातचीत करने के विचार के प्रति अधिक ग्रहणशील होने के लिए प्रोत्साहित किया है।

1998 में, ईरान और अफगानिस्तान में तत्कालीन तालिबान शासन के बीच युद्ध की स्थिति लगभग बन गई थी, जब तालिबान द्वारा कथित तौर पर नौ ईरानी राजनयिकों की हत्या कर दी गई थी।[36] हालाँकि, **9/11** और अफगानिस्तान में नाटो/संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ तालिबान विद्रोह के बाद, ईरानी-अफगान तनाव पीछे छूट गया, क्योंकि तेहरान ने वहाँ अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के लिए तालिबान द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों का स्वागत किया। हालाँकि, तेहरान और तालिबान के बीच संबंधों ने 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था।[37] उस समय से, ईरान ने धीरे-धीरे तालिबान के साथ अपने संपर्कों को सार्वजनिक कर दिया। अफगान गणराज्य के पतन से एक महीने पहले, ईरान ने अफगानिस्तान के संकट का राजनीतिक समाधान खोजने के

लिए तेहरान में अफगान सरकार के प्रतिनिधि और तालिबान के बीच एक वार्ता की मेजबानी की थी।[38]

ईरान, चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो, हमेशा से ही अफगानिस्तान को लेकर चिंतित रहा है, लेकिन बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और तनावपूर्ण आंतरिक वातावरण ने तेहरान को तालिबान के साथ

बातचीत करने के विचार के प्रति अधिक ग्रहणशील होने के लिए प्रोत्साहित किया है। तालिबान में सत्ता में

"Iran Holds Taliban Responsible for 9 Diplomats' Deaths." New York Times, September 11, 1998. Available at: https://www.nytimes.com/1998/09/11/world/iran-holds-taliban-responsible-for-9-diplomats-deaths.html

36 "Why did the Taliban go to Tehran?" The Guardian, May 22, 2015. Available at: https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/may/22/taliban-delegation-official-visit-tehran-iran-isis

37 "In Tehran talks, Iran offers help to resolve Afghan crisis" Reuters, July 7, 2021. Available at: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tehran-talks-iran-offers-help-resolve-afghan-crisis-2021-07-07/

आने के बाद, ईरानी अधिकारियों ने सुन्नी चरमपंथी समूह, जिसे लंबे समय से ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाता रहा है, के साथ संबंधों को उचित ठहराने के लिए तालिबान को एक 'सुधारित समूह' के रूप में पुनः ब्रांड करना शुरू कर दिया ।[39]

ईरान का तालिबान के साथ जुड़ाव भू-आर्थिक प्रेरणाओं से भी प्रभावित है। वर्ष 2022-2023 के लिए निर्यात और आयात पर तालिबान प्रशासन द्वारा जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि ईरान का सबसे बड़ा (20 प्रतिशत) हिस्सा है और यह अफ़गान सामानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य भी है (नीचे तालिका 1 देखें)।[40] 2023 के अंत में, ईरान और अफ़गानिस्तान ने परिवहन, नागरिक उड्डयन, खनन और मुक्त व्यापार क्षेत्रों से संबंधित पाँच आर्थिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए।[41]

तालिका 1: अफ़गानिस्तान के आयात और निर्यात के सबसे बड़े स्रोत (अप्रैल 2023-2022) मिलियन अमेरिकी डॉलर में

अफ़गानिस्तान का आयात		अफ़गानिस्तान का निर्यात	
ईरान	1.472	पाकिस्तान	1.225
पाकिस्तान	1.164	भारत	417
चीन	1.135	उज़्बेकिस्तान	49
यूएई	831	तजाकिस्तान	39
तुर्कमेनिस्तान	480	यूएई	37
कज़ाखस्तान	281	ईरान	28
रूस	271	इराक़	23

उज़्बेकिस्तान	232	तुर्किये	18
भारत	218	कज़ाखस्तान	13

(Date Source: Sputnik Afghanistan)

39 Ali Fathollah-Nejad and Hamidreza Azizi, "Iran and Taliban After the US Fiasco in Afghanistan," The Middle East Institute, September 22, 2021, https://www.mei.edu/ publications/iran-and-taliban-after-us-fiasco-afghanistan

40 Sputnik Afghanistan, "Подробный перечень основных импортеров афганских товаров в прошлом году [Detailed List of the Main Importers of Afghan Goods Last Year]," Telegram post, March 31, 2023, https://t.me/sputnikaf/20534; Sputnik Afghanistan, "Кто продал в Афганистан больше всех товаров? [Who sold the most goods to Afghanistan?]," Telegram post, April 13, 2023, Available at:https://t.me/sputnikaf/20825

41 "Exploring Iran-Afghanistan collaboration: Kabul's Pursuit of Trade Diversification". Special Eurasia, December 4, 2023. Available at: https://www.specialeurasia.com/2023/12/04/iran-afghanistan-cooperation/

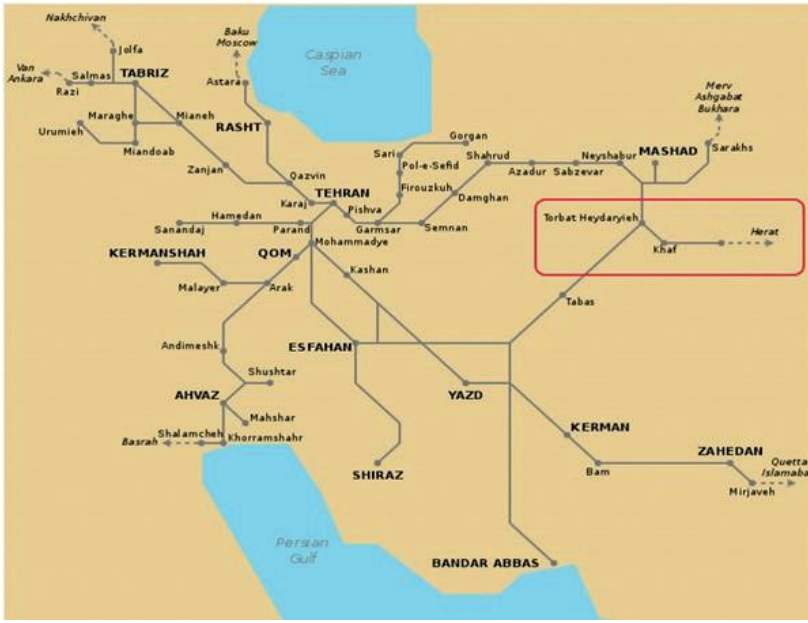

मानचित्र **2.** खवाफ-हेरात रेलवे परियोजना

अक्टूबर 2023 में, काबुल में ईरान के राजदूत ने संकेत दिया कि तेहरान और काबुल ने पारगमन क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए व्यापार विकास के लिए ईरान-अफगानिस्तान चैंबर बनाने पर सहमति व्यक्त की है।[42] इसके अलावा, अफगानिस्तान रेलवे प्राधिकरण ने खवाफ-हेरात रेलवे के उपयोग के संबंध में ईरानी रेलवे कंसोर्टियम के साथ सहमति व्यक्त की है (मानचित्र 2 देखें)। समझौते के अनुसार, ईरान की योजना प्रारंभिक वर्ष में इस मार्ग से 100,000 टन माल परिवहन करने की है, तथा उसके बाद प्रतिवर्ष 100,000 टन की वृद्धि होगी।[43] दोनों पक्षों ने अतिरिक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसका

दायित्व पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग में अवरोध उत्पन्न करने वाली किसी भी बाधा की पहचान करना होगा।

42 Ibid
43 Ibid

ईरान और तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार के स्तर को प्रति वर्ष 10 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी सहमति व्यक्त की।[44] पारगमन भी अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसका आर्थिक और भू-राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्व है। भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तत्व है।[45] ईरान और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक संबंधों की संभावनाओं की जाँच करते समय ऊर्जा एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। ईरान से ऊर्जा और ईंधन निर्यात में, विद्युत शक्ति और गैसोलीन दोनों में, सापेक्ष प्रभुत्व बनाए रखने की उम्मीद है।[46] इन कारकों ने ईरान को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को आकार देने के लिए आर्थिक लाभ भी प्रदान किया है। इसके अलावा, ईरान और अफगानिस्तान के बीच सहयोग

बढ़ाने की संभावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे दो देशों के लिए व्यापार बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने का मार्ग प्रदान करता है।

ईरान को उम्मीद थी कि तालिबान सीमा पर घुसपैठ, ईरान में आने वाले अफगान शरणार्थियों की आमद, ईरान के पूर्वी प्रांतों में जलापूर्ति बनाए रखने, आईएसआईएस-खोरासान आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और एक समावेशी सरकार बनाने से संबंधित ईरान की सुरक्षा और राजनीतिक चिंताओं पर विचार करेगा। अभी तक ईरान की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ईरान और तालिबान शासित अफ़गानिस्तान के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:

"Iran, Afghanistan Ink 5 Economic Co-op MOUs," Tehran Times, November 10, 2023, https://www.tehrantimes.com/news/491175/Iran-Afghanistan-ink-5-economic-co-op- MOUs

44 On May 13, 2024, India Ports Global Limited and the Ports and Maritime Organization of Iran signed a 10-year deal that allows New Delhi to develop and operate the Iranian port of Chabahar.

45 Vali Golmohammadi "Turbulent Geopolitics, Uneasy Neighbour: Iran's Pragmatic Engagement with the Taliban" in Afghanistan Under the Taliban: Enduring Challenges, evolving Responses. ORF Special Report, no.223, March 2024.

सप्रू
हाउस
पेपर

1. फ़्रीक्वेनी सीमा झड़पें

अफगानिस्तान में तालिबान के वर्तमान शासन के दौरान, तालिबान बलों और ईरानी सीमा रक्षकों के बीच कई छोटी-मोटी सीमा झड़पें हुई हैं, साथ ही चार महत्वपूर्ण संघर्ष भी हुए हैं। पहली बड़ी घटना दिसंबर 2021 में ईरान के हिरमंद काउंटी में स्थित शांगलाक गांव में हुई, जहां तालिबान सीमा बलों ने गलती से ईरानी किसानों को निशाना बनाया, जो ईरानी क्षेत्र में थे। ईरानी मीडिया ने ऐसी घटनाओं के लिए तालिबान के खराब प्रशिक्षित सीमा रक्षकों को जिम्मेदार ठहराया, तथा कहा कि वे ईरान-अफगानिस्तान संबंधों की जटिलताओं से अनभिज्ञ हैं। दूसरी बड़ी झड़प अप्रैल 2022 में हेरात के काला जिले में हुई, जिसके कारण ईरानी सीमा चौकी को बंद करना पड़ा। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार, सोशल मीडिया फुटेज में दिखाया गया है कि झड़प के बाद ईरान ने सीमा पर सैन्य वाहन तैनात कर दिए हैं।

Map 3. Milak- Zaranj Border Crossing between Iran and Afghanistan

Turkmenistan
Ashgabat
Mashhad
Dushanbe
Tajikistan
Mary
Dogharoun
crossing
Herat
Kabul
Afghanistan
Mahiroud
crossing
Iran
Milak crossing
Kandahar
Pakistan
Multan
Zahedan

जुलाई 2022 में, तीसरी घटना अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में सीमा पर गोलीबारी के बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक अफगान सैनिक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। रिपोर्टों से पता चला है कि तालिबान बलों ने ईरानी क्षेत्र में अपना झंडा फहराने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष मई 2022 में हुआ, जब अफगान और ईरानी गार्डों के बीच घातक टकराव में कम से कम दो ईरानी और एक अफगान मारे गए, दोनों पक्षों ने हिंसा शुरू करने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया। जवाब में ईरान ने मिलक-जरंज सीमा चौकी को बंद कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक चौराहा था ।

1. ईरान में अफगान शरणार्थियों का प्रवाह

अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के समय, यह अनुमान लगाया गया था कि ईरान में 3 मिलियन से अधिक अफगान शरणार्थी थे, जिनमें से 780,000 पंजीकृत हैं और अन्य 586,000 पासपोर्ट और वीज़ा के साथ प्रवेश पा चुके हैं।[47] गैर-पंजीकृत शरणार्थियों की कोई सटीक गणना नहीं है, न यह पता है कि वे कहाँ रहते हैं या क्या करते हैं। हालाँकि, ईरान में शरणार्थी अफगानिस्तान के सभी क्षेत्रों से आते हैं और सभी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि वे ज्यादातर ताजिक (फारसी भाषी) या

हजारा (अफगानिस्तान में उत्पीड़न झेल रहे शिया मुसलमान) हैं। ईरान में अफगान शरणार्थियों की अधिकांश आबादी प्रमुख शहरों के आसपास केंद्रित है, जहां वे निम्न-स्तरीय निर्माण व्यवसायों में काम खोजने का प्रयास करते हैं।[48] तालिबान के कब्जे के साथ ही ईरान भागने वाले अफगानों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। 2021 में, नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद ने अनुमान लगाया कि हर दिन 4,000-5,000 अफगान ईरान भाग रहे थे।[49]

47 "Refugees in Iran". UNHCR Country Profile. Available at: https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/

48 "Iran and Afghanistan: Growing Tensions after the Return of the Taliban." E-International Relations, August 23, 2022. Available at: https://www.e-ir.info/2022/08/23/iran-and-afghanistan-growing-tensions-after-the-return-of-the-taliban/

49 "*Iran Deporting Thousands of Afghan Refugees.*" Al Jazeera, November 11, 2021.Avai

इनमें से अधिकांश ने ज़रांज के पास दक्षिणी सीमा के आसपास अवैध रूप से ईरान में प्रवेश करने का प्रयास किया। रिपोर्टों के अनुसार ज़रांज में अफ़गानों की भीड़ उमड़ पड़ी है जो ईरान में अवैध रूप से घुसने के लिए आए हुए हैं।[50] हालाँकि इसकी शरणार्थी नीति अपेक्षाकृत समावेशी रही है, इसने कई शरणार्थियों को कभी स्वेच्छा से और अक्सर बलपूर्वक अफ़गानिस्तान वापस भेजा है। मार्च 2023 में, अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 11 शरणार्थियों को ईरानी गार्डों ने गोली मार दी, जिसके कारण काबुल के अंदर हंगामा और ईरान विरोधी प्रदर्शन हुए।[51] कथित तौर पर, अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे लगभग 100 शरणार्थियों का भी यही हश्र हुआ।[52] कई मामलों में, वापस लौटने वाले शरणार्थी फिर से ईरान भागने का प्रयास करते हैं।[53] शरणार्थियों की स्थिति ने ईरान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पैदा कर दिया है। काबुल टीवी पर ईरानी सीमा रक्षकों द्वारा अफगान शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वीडियो दिखाए गए हैं, जिससे अफगान लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है। काबुल में प्रदर्शनकारियों ने ईरानी दूतावास पर प्रदर्शन किया तथा जरांज स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर पत्थर फेंके।[54] यह शरणार्थी समस्या निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि अधिकाधिक अफगानी भागने

का प्रयास कर रहे हैं और ईरान उन्हें वापस भेजना जारी रखे हुए है।

2. *पानी के न्यायसंगत बंटवारे पर विवाद*

50 "*Choice for Afghans: Over the Wall or Through the Desert.*" France 24, France24, March 9, 2022. *Available at:* https://www.france24.com/en/live-news/20220309-freedom-s-choice-for-afghans-over-the-wall-or-through-the-desert

51 "Iran's Border Guards Kill Afghan Migrants In Sistan and Baluchistan."IRANWIRE, March 16, 2023. Available at: https://iranwire.com/en/news/114836-irans-border-guards-kill-afghan-migrants-in-sistan-and-baluchistan/

52 "Nearly 100 Afghan refugees shot dead by Iranian security forces during past 6 months: Local officials" ANI, February 8, 2022. Available at:https://www.aninews.in/news/world/asia/nearly-100-afghan-refugees-shot-dead-by-iranian-security-forces-during-past-6-months-local-officials20220208222921/

53 "*Amid a crackdown, Afghan Refugees in Iran fear the 'unthinkable': Being sent back".* Los Angeles Times, December 16, 2021. Available at: https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-12-16/afghan-refugees-iran-crackdown-deportation-taliban

54 *For Desperate Afghans, Risky Crossings Into Iran are worth chancing.* The New Humanitarian, May 17, 2022. Available at: https://www.thenewhumanitarian.org/News-feature/2022/05/17/Afghans-risky-crossings-Iran

Map 4. Helmand River Basin

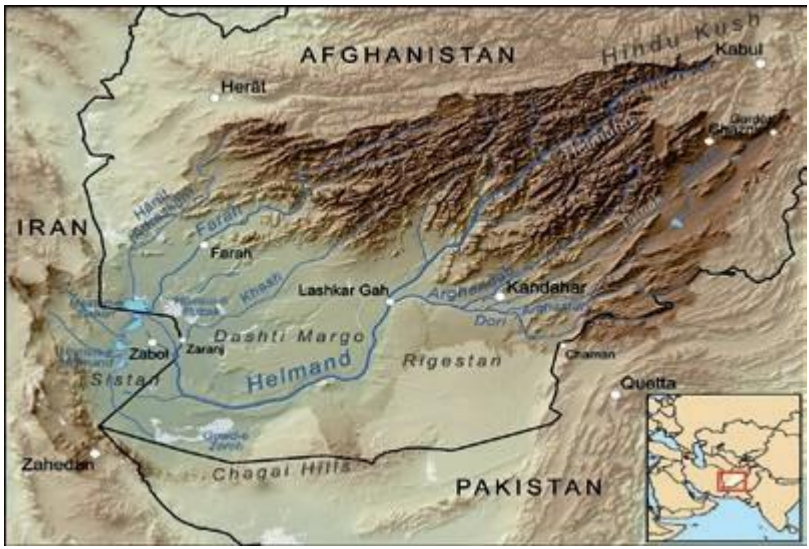

ईरान और अफगानिस्तान के बीच जल विवाद 1870 के दशक से ही शुरू हो गया था, जब अफगानिस्तान ब्रिटिश नियंत्रण में था।[55] एक ब्रिटिश अधिकारी ने हेलमंद नदी की मुख्य शाखा के साथ ईरान-अफगान सीमा खींची। 1939 में, रजा शाह पहलवी की ईरानी सरकार और मोहम्मद ज़हीर शाह की अफ़गानिस्तान सरकार ने नदी के पानी के बंटवारे पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अफ़गानिस्तान इसका अनुसमर्थन करने में विफल रहे। अंततः 1973 में ईरानी प्रधानमंत्री

अमीर अब्बास होवेदा और अफगान प्रधानमंत्री मोहम्मद मूसा शफीक ने अफगान-ईरानी हेलमंद नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अफगानिस्तान को ईरान को प्रतिवर्ष 22 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी देना होगा, साथ ही प्रति सेकंड चार क्यूबिक मीटर पानी देना होगा,

55 "Iran and Afghanistan are feuding over the Helmand River. The water wars have no end in sight."

Atlantic Council, July 7, 2023. Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/iran-afghanistan-taliban-water-helmand/

56 " The Afghan-Iranian Helmand River Water Treaty". 1973. Available at: https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1973_Helmand_River_Water_Treaty-Afghanistan-Iran.pdf

जिससे सामान्य परिस्थितियों में वार्षिक औसत 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति होगी । 2021 में तालिबान के काबुल में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से, हेलमंद नदी का जल बंटवारा पड़ोसी देशों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, खासकर हाल के महीनों में।

1,300 किलोमीटर लंबी हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है (मानचित्र 4 देखें)। इसकी उत्पत्ति हिंदू कुश पर्वतमाला में हुई है और यह दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के सिस्तान दलदलों और हामून झील में जाकर गिरती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हेलमंद नदी एकमात्र नदी है जिस पर अफगानिस्तान ने अपने किसी पड़ोसी के साथ औपचारिक समझौता किया है। मार्च 2021 में कमाल खान बांध के खुलने से हेलमंद नदी में पानी के आवंटन को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच पुराना विवाद फिर से भड़क उठा। ईरान ने दावा किया कि उसे 1973 के समझौते के तहत तय कुल राशि का केवल 4 प्रतिशत ही मिल रहा है।[57]

हेलमंद नदी बेसिन में कई बांध हैं, जैसे कि हेलमंद नदी पर काजाकी, ग्रिश्क और कमाल खान बांध तथा इसकी सहायक नदी अरघंदब पर दहला बांध।[58] हेलमंद नदी के पानी को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव के चरम पर, तालिबान ने एक नई सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें फराह नदी पर बख्शाबाद बांध का निर्माण पूरा करना शामिल था, जो उत्तर से सिस्तान

बेसिन को पानी देती है।[59]

57 "Iran and Afghanistan face off over sharing Helmand waters."MENA, May 28, 2023. Available at: https://www.thenationalnews.com/mena/2023/05/28/iran-and-afghanistan-face-off-over-sharing-helmand-waters/

58 "Afghanistan Clashes with Iran over Dam Construction". The Central Asia-Caucasus Analyst, May 2. 2023 Available at: https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13443-afghanistan-clashes-with-iran-over-dam-construction.html

59 Ibid

ईरान के दक्षिण-पूर्व में निचले स्तर की आर्द्रभूमियों और झीलों को पानी देने वाले ऊपरी जल स्रोतों पर अफगानिस्तान के नियंत्रण के साथ, तालिबान को तेहरान के साथ अपने संबंधों में लाभ उठाने का एक साधन मिल गया है।

20 मई, 2023 को अफगानिस्तान में ईरान के राजदूत हसन काज़मी कोमी ने तालिबान को स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा: 'अगर पानी था और तालिबान ने इसे इस्लामी गणराज्य ईरान की सरकार को उपलब्ध नहीं कराया, तो यह स्पष्ट है कि उसे इस मुद्दे पर कैसे कार्य करना चाहिए'।[60] कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी तालिबान शासकों को कड़े शब्दों में कहा था: 'मैं अफगानिस्तान के शासकों को चेतावनी देता हूं कि वे सिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को पानी के अधिकार दें... हम अपने लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे।'[61] तालिबान के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने 22 मई को जवाब में कहा कि काबुल '1973 की जल संधि के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अफगानिस्तान और क्षेत्र में मौजूद सूखे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए'।[62] ईरान के दक्षिण-पूर्व में निचले स्तर के आर्द्रभूमि और झीलों को पानी देने वाले ऊपरी नदी जल स्रोतों पर अफगानिस्तान के नियंत्रण के साथ, तालिबान को तेहरान के साथ अपने संबंधों में लाभ उठाने का एक साधन मिल गया है। यद्यपि ईरान तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है, फिर भी उसने पड़ोसी तालिबान शासन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। हेलमंद नदी के पानी के मुद्दे ने हाल के महीनों में ईरान और तालिबान के बीच

संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। हालाँकि, तेहरान और काबुल ने फिलहाल हालात को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों पक्षों को एहसास हो गया कि तनाव को और बढ़ाना उनके हित में नहीं होगा।

60 "Iran warns Afghanistan to respect its water rights over Helmand River." Iranwire, May 18, 2023. Available at: https://iranwire.com/en/news/116669-iran-warns-afghanistan-to-respect-its-water-rights-over-helmand-river/

61 Ibid

62 "Iran And Afghanistan's Taliban Clash as Water Dispute Boils Over". Radio Free Europe, May 30, 2023. Availab

अगस्त 2021 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के पतन का सीधा असर देश के मध्य एशियाई पड़ोसियों पर पड़ा, खासकर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पर, शुरू से ही।

फिर भी, हेलमंद नदी जल बंटवारा एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है और इससे निकट भविष्य में भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है।

मध्य एशियाई पड़ोसी

अगस्त 2021 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के पतन का सीधा असर देश के मध्य एशियाई पड़ोसियों पर पड़ा, विशेष रूप से अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों, अर्थात् ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पर, बहुत शुरू से ही। जैसे ही तालिबान ने नियंत्रण हासिल किया, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी शुरू में उज्बेकिस्तान भाग गए [63]; और वहां से अबू धाबी। लगभग उसी समय, अफगान वायु सेना के 50 से अधिक सदस्यों ने अपने विमान ताजिकिस्तान में उतारे, जबकि अधिक विमान उज्बेकिस्तान के तरमेज़ में उतरे।[64] प्रारंभ में, मानवीय एजेंसियों ने मध्य एशिया की सीमाओं से शरणार्थियों के अत्यधिक प्रवाह के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी। हालाँकि, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने केवल कुछ उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों को अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन आम अफगानों को

नहीं।

63 "Afghan President Ghani flees country as Taliban enters Kabul."Al Jazeera, August 15, 2021. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/15/afghan-president-ghani-flees-country-as-taliban-surrounds-kabul

64 "Afghan military aircraft land in Uzbekistan, move to Tajikistan". Center for Strategic International Studies, August 26, 2021. Available at: https://www.csis.org/analysis/afghan-military-aircraft-land-uzbekistan-move-tajikistan-updated

नई वास्तविकताओं का पता लगाना
अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश और तालिबान शासन

भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और सुरक्षा संबंधी
विचारों ने यह सुनिश्चित किया है कि
ताजिकिस्तान को छोड़कर ये देश
अफगान तालिबान शासन
के प्रति बहु-पक्षीय दृष्टिकोण बनाए रखें,
ताकि सहयोग और सहभागिता के लिए
स्थान बनाया जा सके।

ताजिकिस्तान में 10,000 से अधिक रूसी सैनिकों की उपस्थिति से मध्य एशियाई राज्यों और अफगानिस्तान के बीच स्थिरता बनाए रखने और सीमा की सुरक्षा में मदद मिली।

मध्य एशियाई गणराज्यों ने 2021 की गर्मियों में अफगानिस्तान से बाईडेन प्रशासन के अचानक प्रस्थान का स्वागत नहीं किया; उन्होंने अनिच्छा से बदली हुई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाया। तब से, तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के प्रति मध्य एशियाई देशों की नीतियों में कुछ समानताएं देखने को मिली हैं, जिनमें व्यापार-संचालित व्यावहारिकता के साथ-साथ अफगानिस्तान में जिहाद में लगे मध्य एशिया-केंद्रित आतंकवादी समूहों से संबंधित चिंताएं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएँ रही हैं। भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और सुरक्षा संबंधी विचारों ने यह सुनिश्चित किया है कि ताजिकिस्तान को छोड़कर ये देश अफगान तालिबान शासन के प्रति बहु-पक्षीय दृष्टिकोण बनाए रखें, ताकि सहयोग और सहभागिता के लिए स्थान बनाया जा सके। उनके दृष्टिकोण में यह परिवर्तन 1990 के दशक के दौरान प्रथम तालिबान शासन के प्रति उनके कटु रवैये के बिल्कुल

विपरीत है। इस संबंध में, यह देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान के तीन मध्य एशियाई देश पड़ोसी तालिबान शासन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

उज्बेकिस्तान ने **2018** की शुरुआत में तालिबान के साथ संपर्क स्थापित किया था और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के नियंत्रण में आने के बाद उसके साथ सीधी बातचीत शुरू करने वाले पहले देशों में से एक था।

Sapru
House
Paper

इसकी महत्वाकांक्षा व्यापार और आर्थिक संबंधों को पुनः आरंभ करने की है, विशेष रूप से उज्बेकिस्तान द्वारा प्रस्तावित ट्रांस-अफगान रेलवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए। इसने सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अफगान सीमा के निकट तेरेमज़ में एक नया कार्गो केंद्र खोला है।[65] उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से हिंद महासागर तक रेल और सड़क संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जुलाई 2021 में ताशकंद में आयोजित "मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संपर्क: चुनौतियां और अवसर" सम्मेलन में, उज्बेकिस्तान ने टर्मेज़-मजार-ए-शराफ-काबुल-पेशावर रेलमार्ग के विकास का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए लगभग 6 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है और यह चीनी बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा हो सकता है।[66] नवंबर 2023 में, उज्बेक प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार और पारगमन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया, और कथित तौर पर, तालिबान ने उज्बेकिस्तान से मध्य एशियाई देश के माध्यम से माल की आवाजाही के लिए पारगमन

शुल्क कम करने को कहा।[67] अफगानिस्तान के साथ सहयोग करने के लिए उज्बेकिस्तान की तत्परता उन रिपोर्टों से स्पष्ट है, जिनमें एक 'व्यापार मार्ग मानचित्र' का खुलासा किया गया है, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान को निर्यात को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य 'दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को वर्तमान 600 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर लगभग 3

बिलियन डॉलर करना है'।[68] तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उज्बेकिस्तान की बढ़ती प्रतिबद्धता तब भी देखी जा सकती है जब उसने जुलाई 2022 में ताशकंद सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 20 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रमुख विश्व शक्तियां भी शामिल थीं,

65 "Uzbek Border Town Adjusts to the Taliban as Neighbors."VoA, August 15, 2023. Available at: https://www.voanews.com/a/uzbek-border-town-adjusts-to-the-taliban-as-neighbors/7225572.html

66 Skand R Tayal, " Chentral Asia's Connect with Afghanistan" in R. K Sawhney (ed.) " Afghanistan Through the Fog of Instability"(New Delhi, Rupa Publishers, 2022), pp. 62-75.

67 "Trade and Transit Top Agenda as Uzbek Delegation Visits Afghanistan." The Diplomat, November 2, 2023. Available at: https://thediplomat.com/2023/11/trade-and-transit-top-agenda-as-uzbek-delegation-visits-afghanistan/

68 Ibid

शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह है
कि तालिबान और उज्बेकिस्तान के बीच
संबंध कितने सामान्य हैं, इस वास्तविकता
के बावजूद कि ताशकंद सहित किसी भी
सरकार ने अगस्त 2021 में सत्ता में
आने के बाद तालिबान शासन को
आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।

जो तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए एक साथ आए थे। इसे अफगानिस्तान को धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकीकृत करने तथा ऊर्जा और संचार में अवसंरचना सहयोग परियोजनाओं पर काम करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम माना गया। इसके अतिरिक्त, उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान को बिजली आपूर्ति के लिए अपने 10 साल के समझौते को जारी रखने का इच्छुक है। शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि तालिबान और उज्बेकिस्तान के बीच संबंध कितने सामान्य हैं, इस वास्तविकता के बावजूद कि ताशकंद सहित किसी भी सरकार ने अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।

ताजिकिस्तान ऐतिहासिक रूप से तालिबान शासन का सबसे मुखर विरोधी रहा है। उल्लेखनीय रूप से, ऐसे समय (2018-2020) जब उज़बेक, रूस और ईरान समेत अन्य देशों ने दोहा में तालिबान कार्यालय के साथ बातचीत शुरू कर दी थी, ताजिकिस्तान ने तालिबान के साथ संचार का कोई ज्ञात चैनल

नहीं खोला। अगस्त में अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी का सार्वजनिक रूप से विरोध करने वाला ताजिकिस्तान एकमात्र पड़ोसी देश था, जिसने शासन को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ख़तरा बताया था। तालिबान के कब्जे के बाद, ताजिकिस्तान ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संगठन (सीएसटीओ) के सदस्यों के सैनिकों के साथ अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा के पास सैन्य अभ्यास भी किया।[69]

69 "Hostilities Grow Between Taliban And Tajikistan Amid Border Closure, Truck Seizures". RadioFreeEurope, May 19, 2022. Available at: https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-tajikistan-border-truck-seizures/31858508.html

दूसरी ओर, तालिबान ने दुशांबे पर राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा (एनआरएफ) के नेताओं की मेजबानी और समर्थन करने का आरोप लगाया है और यहाँ तक कि ताजिकिस्तान को धमकी दी है कि अगर दुशांबे ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना जारी रखा तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद, ताजिकिस्तान ने पश्तून-प्रभुत्व वाले अनंतिम तालिबान मंत्रिमंडल में जातीय ताजिक को शामिल करने की जोरदार माँग की। अतीत में, इसने अपने साथी ताजिक नेता अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाली तालिबान विरोधी प्रतिरोध बलों और बाद में मसूद के बेटे के नेतृत्व वाली एनआरएफ का समर्थन किया था। ताजिकिस्तान ने सितंबर 2021 में पूर्व अफगान राष्ट्रपति बुरहुनुद्दीन रब्बानी और पूर्व रक्षा मंत्री, पंजशीर के दिवंगत शेर अहमद शाह मसूद को देश के सर्वोच्च सम्मान, 'द ऑर्डर ऑफ इस्माइली सोमोनी' से सम्मानित करके ताजिक अफगान प्रतिरोध को समर्थन का एक महत्वपूर्ण संकेत दिया। वास्तव में, इस पुरस्कार के लिए दर्शक अफगानिस्तान के अंदर की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने या उस पर कोई प्रभाव डालने के बजाय घरेलू स्तर पर ही अधिक थे। 1990 के दशक में सत्ता में आने के बाद से रहमोन ने ताजिक राष्ट्रवाद को संगठित करने का प्रयास किया है, यह

प्रयास हाल के वर्षों में और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ताजिकिस्तान को अपने पड़ोसी किर्गिस्तान के साथ आर्थिक कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ताजिकिस्तान ने अफ़गान तालिबान पर जमात अंसारुल्लाह (जेए) और तहरीक-ए-तालिबान ताजिकिस्तान (टीटीटी) जैसे आतंकवादी समूहों की मेजबानी करने का आरोप लगाया है, जिनका उद्देश्य देश को अस्थिर करना है। जनवरी में, ताजिक राष्ट्रपति ने सीएसटीओ से अफगानिस्तान के चारों ओर एक सुरक्षा बेल्ट बनाने का आग्रह किया था, तथा दावा किया था कि उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में 40 से अधिक आतंकवादी शिविर हैं, जिनमें लगभग 6,000 आतंकवादी हैं। गोर्नो बदख्शां से तालिबान ने अपने साथियों के रूप में भर्ती ने दुश्मनी को

और बढ़ा दिया है।[70] इस तरह के समावेश का मुख्य कारण गोर्नो बदख्शां की आबादी और ताजिक सरकार के बीच संघर्ष है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सुरक्षा मुद्दों के अलावा, अफ़गानिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी मध्य एशियाई देशों, विशेष रूप से ताजिकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अनुमानतः 30 प्रतिशत मादक पदार्थ अफगानिस्तान से रूस तक मध्य एशिया के रास्ते, मुख्यतः ताजिकिस्तान के रास्ते पहुँचते हैं।[71] संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जब से तालिबान ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया है, तब से यह देखा गया है कि अफगानिस्तान से पड़ोसी देशों में सिंथेटिक ड्रग (जैसे मेथामफेटामाइन) की तस्करी में वृद्धि हुई है, तथा पिछले पांच वर्षों में ड्रग की जब्ती में लगभग बारह गुना वृद्धि हुई है।[72] ताजिकिस्तान अफीम की सबसे बड़ी मात्रा जब्त करने वाले देशों में 11वें स्थान पर है और स्वाभाविक रूप से वह इसके दुष्परिणामों को लेकर चिंतित है।

हालाँकि, पिछले वर्ष कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो राजनयिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल

ने 2023 की शुरुआत में दुशांबे का दौरा किया, जिसकी ताजिक सरकार द्वारा न तो पुष्टि की गई

70 "The Dynamics of Central Asian Engagement with the Taliban Government."MP-IDSA, February 19, 2024. Available at: https://www.idsa.in/idsacomments/the-dynamics-of-central-asian-engagement-jwahlang-190224

71 "Central Asia and the Transition in Afghanistan". COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS, US Senate, 2021. Available at: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-112SPRT71639/html/CPRT-112SPRT71639.htm#:~:text=According%20to%20U.S.%20officials%2C%20an,human%20capacity%2C%20and%20porous%20borders.

72 "UNODC: Methamphetamine trafficking in and around Afghanistan expanding rapidly as heroin trade slows".UNODC, September 10, 2023. Available at: https://unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2023/unisnar1476.html#:~:text=KABUL%2FVIENNA%2C%2010%20September%20(,today%20by%20the%20United%20Nations

ताजिकिस्तान ने अब तक बदले में काबुल में कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है, लेकिन उसने अफगानिस्तान को बिजली का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है, उसने आर्थिक सहयोग और पीड़ित अफगान जनता की मदद का हवाला दिया है, जबकि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ राजनीतिक सहयोग को अस्वीकार कर दिया है।

और न ही खंडन किया गया।[73] यह ज्ञात है कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राजनयिक वीजा पर नहीं बल्कि व्यावसायिक वीजा पर यात्रा कर रहे थे। तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की और स्वायत्त गोर्नो-बदख्शां क्षेत्र की राजधानी और अफगान बदख्शां क्षेत्र के सीमावर्ती शहर खोरोग में पूर्व वाणिज्य दूतावास का दौरा किया, मार्च में, जो पिछले महीने हिमस्खलन के कारण नष्ट हो गया था।[74] ताजिकिस्तान ने अब तक बदले में काबुल में कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है, लेकिन उसने अफगानिस्तान को बिजली का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है, उसने आर्थिक सहयोग और पीड़ित अफगान जनता की मदद का हवाला दिया है, जबकि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ राजनीतिक सहयोग को अस्वीकार कर दिया है।

तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के साथ **744** किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और अब तक तटस्थता की विदेश नीति अपनाता रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद, तुर्कमेन सरकार ने सीमा व्यापार की अनुमति दे दी। तुर्कमेनिस्तान 1,814 किलोमीटर लम्बी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत (टीएपीआई) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को क्रियान्वित करने का इच्छुक है, जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष लगभग 33 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर तुर्कमेन गैस का निर्यात करना है।

73 "Taliban Claims Delegation Visited Afghan Consulate In Neighboring Tajikistan." RadioFreeEurope, March 26, 2023. Available at: https://www.rferl.org/a/afghanistan-tajikistan-consulate-visit/32334909.html

74 Ibid

पारंपरिक ज्ञान के विपरीत, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के पतन और क्षेत्र से अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी से सुरक्षा शून्यता नहीं पैदा हुई। इसके बजाय, अधिक आत्मविश्वास से भरा मध्य एशिया, तालिबान के साथ सीधे तौर पर उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हुआ जो कई सालों या शायद दशकों से रुकी हुई थीं।

इसके अलावा सीएएसए-1000 नामक मध्य एशिया-दक्षिण एशिया विद्युत परियोजना भी है, जो ताजिकिस्तान और किर्गिजस्तान से अतिरिक्त जलविद्युत पॉवर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में निर्यात करेगी। दक्षिण एशिया बिजली परियोजना, जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से अतिरिक्त जलविद्युत पॉवर को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में निर्यात करेगी। अफ़गानिस्तान को न केवल बिजली की उपलब्धता से बल्कि पारगमन शुल्क से भी लाभ होगा। तुर्कमेन नेतृत्व वर्तमान में तालिबान शासन के साथ अच्छे संबंधों की तलाश कर रहा है। यह अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता और बिजली प्रदान करता है और तालिबान द्वारा सरकार पर कब्ज़ा करने को मान्यता देने वाला पहला मध्य एशियाई देश था।[75]

कुल मिलाकर, सत्ता में लौटने के बाद तालिबान अफगानिस्तान में अपेक्षाकृत शांति का युग लाने में सफल रहा है। बदले में, इससे मध्य एशिया के साथ सहयोग का युग शुरू हुआ है। पारंपरिक

ज्ञान के विपरीत, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के पतन और क्षेत्र से अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी से सुरक्षा शून्यता की स्थिति पैदा नहीं हुई। इसके बजाय, अधिक आत्मविश्वास से भरा मध्य एशिया, तालिबान के साथ सीधे तौर पर उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हुआ जो कई वर्षों से, या शायद दशकों से, रुकी हुई थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस से संकेत लेने के बजाय, मध्य एशिया के राज्यों, विशेषकर उज्बेकिस्तान ने अपना स्वयं का मार्ग निर्धारित किया है। यह बढ़ता सहयोग द्विपक्षीय व्यापार के बढ़ते स्तर के

75 "Turkmenistan: Berdymukhamedov passes the mantle (and phone)."Eurasianet, March 22, 2022. Available at: https://eurasianet.org/turkmenistan-berdymukhamedov-passes-the-mantle-and-phone

साथ-साथ रुकी हुई क्षेत्रीय अवसंरचना और ऊर्जा परियोजनाओं के पुनरुत्थान और पुनरोद्धार में प्रकट होता है, जो लंबे समय से मध्य एशियाई राज्यों का सपना रहा है। फिर भी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अफगानिस्तान और उसके तीन निकटतम मध्य एशियाई पड़ोसियों के बीच संबंधों में खटास पैदा कर रहे हैं।

1. *कोश टेपा वायर नहर परियोजना*

पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कोश तेपा जल नहर परियोजना के कार्यान्वयन को तालिबान ने जारी रखा है। तालिबान ने 31 मार्च, 2022 को घोषणा की कि अमुदर्या नदी के पानी का उपयोग करने के लिए एक नहर परियोजना शुरू की गई है।[76] यह 280 किलोमीटर लम्बी, 100 मीटर चौड़ी और 8.5 मीटर गहरी माना जाता है। एक बार पूरा हो जाने पर, इससे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा से लगे बल्ख, जौज़जान और फरयाब प्रांतों की 550 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने का अवसर मिलेगा। इसकी कुल लागत लगभग 680 मिलियन डॉलर (60 बिलियन अफ़्रीकी डॉलर) आंकी गई है।[77] तालिबान ने इस परियोजना को बहुत महत्व दिया है और इसे

'राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण परियोजना' कहा है।[78] यह कहा जा सकता है कि वे इस परियोजना को अफगानिस्तान के लोगों को सेवा प्रदाता के रूप में स्वयं को साबित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि वे अपने आंतरिक

वित्तपोषण से निर्धारित समय से पहले चरण-1 का निर्माण करने में कामयाब रहे हैं, तालिबान देश के विकास में आत्मनिर्भरता को उजागर करने का प्रयास कर रहा है।

76 "The Qosh Tepa Irrigation Canal project in the north of the country has been progressing quickly." Deputy Prime Minister of Economic Affairs, Islamic Emirate of Afghanistan, website, January 2, 2023. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=GJmitmg4k_w&ab_channel=%40FDPM_AFG.

77 "Taliban's Qosh Tepa Canal Step".Ankara Centre for Crisis and Policy Studies, June 3, 2023. Available at: https://www.ankasam.org/the-talibans-qush-tepa-canal-step/?lang=en

78 "Baradar assess progress of key Qosh Tepa Canal,"ATN News, March 8. 2023, https://www.ariananews.af/baradar-assess-progress-of-key-qosh-tepa-canal/, (accessed 25 July 2023)

Qosh Tepa Water Canal Project Plan

Source: Radio Free Europe

इस कारण, नहर को यथाशीघ्र पूरा करने और कार्यान्वित करने के लिए 120 स्थलों पर एक साथ गहन गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं।[79]

मध्य एशिया में जल असुरक्षा पहले से ही बढ़ रही है, जहाँ क्षेत्र की एक तिहाई आबादी को सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं है। एक बार कोश टेपा नहर पूरी हो जाने पर, अरल बेसिन पर दबाव और बढ़ जाएगा। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष अमु दरिया से लगभग 10-13 बीसीएम जल का अपवर्तन करना है (लगभग 10-15 प्रतिशत), जिसमें अपवर्तन की उच्चतम मात्रा (लगभग 9.5 बीसीएम) मई से अगस्त तक के चरम सिंचाई मौसम में होगी।[80] The reduction of Amu Darya's flow

79 "The Qosh Tepa Irrigation Canal project in the north of the country has been progressing quickly." Deputy Prime Minister of Economic Affairs, Islamic Emirate of Afghanistan, website, January 2, 2023. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=GJmitmg4k_w&ab_channel=%40FDPM_AFG.

80 Charting Complex Currents: The Qush Tepa Canal and Central Asia's Water. New Security Beat, August

18, 2023. Available at: https://www.newsecuritybeat.org/2023/08/charting-complex-currents-qush-tepa-canal-central-asias-water/

तालिबान ने कई विदेशी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जिनमें जमात अंसारुल्लाह (जेए), इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान (आईएमयू) और इस्लामिक जिहाद यूनियन (आईजेयू) जैसे समूह शामिल थे, जिनके अपने मध्य एशिया केंद्रित एजेंडे थे।

अमु दरिया के प्रवाह में कमी से कृषि को खतरा पैदा हो सकता है, पानी की कमी बढ़ सकती है, तथा मध्य एशिया में सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति बिगड़ने का खतरा हो सकता है। निस्संदेह इसका प्रभाव उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के निचले क्षेत्रों पर पड़ेगा, विशेषकर उनके कृषि, मत्स्य पालन और कपास उद्योगों पर। इसके अलावा, तालिबान द्वारा जिस तीव्र गति से परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उससे भी परियोजना की प्रभावकारिता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। कथित तौर पर, कोश तेपा में लाइनिंग नहीं है, जिसका अर्थ है कि नहर का 60 प्रतिशत पानी रिसाव के कारण नष्ट हो सकता है और जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।[81] उज्बेकिस्तान (और कुछ हद तक तुर्कमेनिस्तान) ने पहले ही नहर के मुद्दे पर इसके संभावित प्रभावों के कारण तालिबान के साथ बातचीत की है, लेकिन द्विपक्षीय दृष्टिकोण से क्षेत्रीय सीमापार जल चुनौतियों का कोई समावेशी समाधान नहीं निकल पाया है। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगस्त में तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों के बीच पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक के दौरान, भाग लेने वाले देशों के लिए जल संसाधनों पर सहयोग एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा।[82] कोश तेपा

नहर पर तालिबान के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण से परिणाम सामने आएंगे या नहीं, यह तो बाद में ही पता चलेगा।

2. *मध्य एशिया के लिए आतंकवाद का खतरा*

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध मॉनिटर ने अप्रैल 2024 में रिपोर्ट दी थी कि 'अफगानिस्तान में अफ़गानिस्तान में आतंकवादी समूहों का अत्यधिक रूप से जमावड़ा क्षेत्र में सुरक्षा

81 "Afghanistan Seeks to Control Its Own Water Destiny." The Diplomat, May 6, 2023. Available at: https://thediplomat.com/2023/05/afghanistan-seeks-to-control-its-own-water-destiny/

82 "A Perspective on First Sub-Regional Trilateral Summit in Central Asia." ICWA View Point, August 28, 2023. Available at: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=9872&lid=6309.

स्थिति को कमजोर करता है।'[83] ऐसे दो सबसे प्रमुख समूह

इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत (आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट का अफगानिस्तान स्थित सहयोगी) और अल कायदा (एक्यू) हैं। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल में सत्ता पर कब्जा किया, तो उन्होंने वादा किया कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल पड़ोसी देशों या किसी अन्य देश के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। यह प्रतिज्ञा पड़ोसी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस वादे में विश्वसनीयता का अभाव था। तालिबान ने कई विदेशी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जिनमें जमात अंसारुल्लाह (जेए), इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान (आईएमयू) और इस्लामिक जिहाद यूनियन (आईजेयू) जैसे समूह शामिल थे, जिनके अपने मध्य एशिया केंद्रित एजेंडे थे।

उदाहरण के लिए, जेए (जिसे 'ताजिक तालिबान' के नाम से भी जाना जाता है), एक ताजिक इस्लामवादी आंदोलन है जो वर्तमान में अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में स्थित है और इसका उद्देश्य ताजिकिस्तान में रहमोन सरकार को गिराना है।[84] जुलाई 2021 में, जब तालिबान अफगानिस्तान में प्रांतों पर कब्जा कर रहा था, तब यह बताया गया था कि तालिबान ने बदख्शां प्रांत में ताजिक सीमा के पास तालिबान द्वारा कब्जा किए गए पांच जिलों में

सुरक्षा का प्रभार जेए को सौंप दिया था।[85] कथित तौर पर, जेए आतंकवादी वर्तमान में वीडियो का उपयोग करके ताजिक देशवासियों से सरकार

के खिलाफ हथियार उठाने और आतंकवाद के आरोप से न डरने का आह्वान कर रहे हैं। एक वीडियो में अफगानिस्तान को 'ऐसा देश जहां मुजाहिदीन शासन करते हैं' कहा गया है, जिससे तालिबान सरकार के प्रति समूह की आत्मीयता पर प्रकाश डाला गया है।[86]

83 "Terrorist Groups in Afghanistan". Congressional Research Service, April 2, 2024. Available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10604#:~:text=Reports%20on%20Terrorism.-,U.N.,response%20to%20Chinese%20government%20concerns.

84 "Tajikistan Seeks Regional Partners to Counter Threats from Afghanistan." The Jamestown Foundation, October 31, 2023. Available at: https://jamestown.org/program/tajikistan-seeks-regional-partners-to-counter-threats-from-afghanistan/

85 "Taliban Puts Tajik Militants Partially In Charge Of Afghanistan's Northern Border." Radio Free Europe, July 27, 2021. Available at: https://www.rferl.org/a/taliban-tajik-militants-border/31380098.html

86 Ibid

यह सितंबर 2023 की शुरुआत में दावराज जिले में अफगान सीमा पार करने के जेए के प्रयास के बाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तीन आतंकवादियों की मौत हो गई और साथ ही हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक जखीरा जब्त किया गया।[87] जुलाई 2022 में टीटीटी की स्थापना ने दुशांबे को और चिंतित कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफ़गानिस्तान से जुड़े मध्य एशिया में सुरक्षा की स्थिति किस तरह से खराब हुई है।[88] टीटीटी का गठन कथित तौर पर उत्तरी अफगानिस्तान में ताजिकिस्तान के लोगों को तालिबान ब्रांड के तहत एकजुट करने और दुशांबे में रहमोन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया है। इसका नेता मेहदी अरसलान उर्फ मोहम्मद शारिपोव है, जो ताजिकिस्तान का निवासी है और पहले अफगानिस्तान चला गया था, जहाँ उसने अफगान तालिबान के साथ लड़ाई लड़ी थी।[89]

आईएमयू उज्बेकिस्तान में सरकार को गिराने के लिए प्रतिबद्ध है और एक समय अल-कायदा का प्रमुख सहयोगी था। 2001 में अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू होने के बाद अल-कायदा का ध्यान अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर केंद्रित हो गया। संयुक्त राष्ट्र

प्रतिबंध मॉनिटर ने बताया कि तालिबान शासन के तहत आईएमयू को अन्य मध्य एशियाई आतंकवादी समूहों के साथ अफगानिस्तान में 'आवागमन की अधिक स्वतंत्रता' प्राप्त है।[90] आईजेयू एक अन्य चरमपंथी संगठन है जो 2000 के दशक के प्रारंभ में आईएमयू से अलग हो गया था

87 "Tajikistan kills 3 Jamaat Ansarullah militants on Afghanistan border" Kabul Now, September 6, 2023. Available at: https://kabulnow.com/2023/09/tajikistan-kills-3-jamaat-ansarullah-militants-on-afghanistan-border/

88 "Tajikistan Faces Threat from Tajik Taliban". The Central Asia-Caucasus Analyst, March 27, 2023. Available at: https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13750-tajikistan-faces-threat-from-tajik-taliban.html

89 "Tehrik-e Taliban Tajikistan and terrorist threat in Tajikistan and Central Asia." Special Eurasia, July 25, 2022. Available at: https://www.specialeurasia.com/2022/07/25/tehrik-e-taliban-tajikistan/

90 "Terrorist Groups in Afghanistan". Congressional Research Service, April 2, 2024. Available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10604#:~:text=Reports%20on%20Terrorism.-,U.N.,response%20to%20Chinese%20government%20concerns.

मध्य एशियाई राज्यों के निकट आईएसकेपी,
ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और
टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति
और उनका बढ़ता प्रभाव उनके लिए
गंभीर चिंता के विषय हैं ।

और अब यह अफगानिस्तान में सक्रिय है,
जहाँ यह तालिबान से संबद्ध हक्कानी नेटवर्क
के साथ मिलकर काम करता है।"

मध्य एशियाई राज्यों के निकट आईएसकेपी, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति और उनका बढ़ता प्रभाव उनके लिए गंभीर चिंता के विषय हैं । अप्रैल और मई 2022 में, क्रमशः, आईएसकेपी ने अफगान क्षेत्र से देश के उत्तरी पड़ोसियों उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में रॉकेट दागे।[92] यद्यपि इन रॉकेटों से कोई हताहत नहीं हुआ या वे फटे नहीं, लेकिन हाल के दिनों में यह पहली बार था जब अफगानिस्तान से उज्बेक क्षेत्र पर हमला किया गया था। आईएसकेपी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और मध्य एशियाई लोगों को भर्ती करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि चीन, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और

तुर्कमेनिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमाओं पर आईएसकेपी के प्रशिक्षण शिविर स्थापित हो गए हैं।[93] यद्यपि टीटीपी की गतिविधियां मध्य एशिया केंद्रित नहीं हैं, फिर भी जून 2023 में हुए एक घटनाक्रम ने मध्य एशियाई राजधानियों में

समूह के संबंध में चिंताएं पैदा कर दी हैं। खबर सामने आई कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत टीटीपी सदस्यों

91 "Central Asia and Central Eurasia Terrorism". Available at: https://www.dni.gov/nctc/groups/central_eurasia.html

92 "Islamic State Khorasan Claims Rocket Attack on Uzbekistan", VoA, April 18, 2022. Available at: https://www.voanews.com/a/islamic-state-khorasan-claims-rocket-attack-on-uzbekistan-/6534866.html

93 "The Islamic State's Central Asian Contingents and Their International Threat".Hudson Institute, Oct 16, 2023. Available at: https://www.hudson.org/foreign-policy/islamic-states-central-asian-contingents-their-international-threat

को पाकिस्तान की सीमाओं से दूर रखने के लिए उन्हें अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा।[94] नियोजित स्थानांतरण में टीटीपी लड़ाके और उनके परिवार के सदस्यों सहित लगभग 72,000 व्यक्ति शामिल होंगे।[95] कथित तौर पर, लगभग 300 व्यक्तियों को पहले ही ताजिकिस्तान सीमा के करीब उत्तरपूर्वी प्रांत तखर में बसाया जा चुका है, जिसके कारण क्षेत्र के मुख्य रूप से उज्बेक निवासियों के साथ झड़पें हो रही हैं।[96] अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद, मध्य एशियाई देशों ने गैर-सरकारी तत्वों को उत्तरी अफगानिस्तान में गतिविधियां चलाने तथा सीमा पार हमले करने से रोकने के लिए तालिबान पर भरोसा किया है। फिर भी, उत्तरी अफगानिस्तान में आईएसकेपी के लगातार हमलों से पता चलता है कि तालिबान इस्लामिक स्टेट पर नियंत्रण खो रहा है। उत्तरी अफगानिस्तान में बिगड़ता सुरक्षा वातावरण सीमा पार मध्य एशिया के लिए भी बुरी खबर है।

चीन

चीन तालिबान शासन के साथ राजनयिक चैनल खोलने वाले पहले देशों में से एक था और उसने घोषणा की कि वह 'मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक' संबंधों के लिए तैयार है'[97] –हालाँकि, उस त्वरित निर्णय की नींव बहुत पहले ही रख दी गई थी। पिछले कई वर्षों से चीन ने तालिबान के साथ सीधा संवाद बनाए रखा है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई

मौकों पर मुलाकात की है, जो इस्लामी समूह के साथ चीन के मधुर होते संबंधों को रेखांकित करता है।

94 "Pakistan Cautiously Lauds Afghan Taliban's Moves to Counter Cross-Border Terrorism." Voice of America, July 18, 2023. Available at:https://www.voanews.com/a/pakistan-cautiously-lauds-afghan-taliban-s-moves-to-counter-cross-border-terrorism-/7172654.html(Accessed on 25.8.23)

95 Taliban, Pakistan Reach Settlement on TTP Members' Relocation to Northern Afghanistan, Khaama Press, June 13,2023. Available at: https://www.khaama.com/taliban-pakistan-reach-settlement-on-ttp-members-relocation-to-northern-afghanistan/

96 Ibid

97 "China ready for 'friendly relations' with Taliban, welcomes Afghan development projects. "France 24, August 16, 2021. Available at: https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210816-china-ready-for-friendly-relations-with-taliban-welcomes-afghan-development-projects (Accessed on 9.4.2022)

चीन सितंबर 2023 में अफगानिस्तान में
अपना राजदूत नियुक्त करने वाला
पहला देश बन गया, जिससे यह अटकलें लगाई
जाने लगीं कि क्या ये घटनाक्रम अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता
देने के लिए
चीन की तत्परता का संकेत हैं।

तालिबान के कब्जे से कुछ दिन पहले, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तियानजिन में तालिबान प्रतिनिधिमंडल के साथ एक हाई-प्रोफाइल बैठक की मेजबानी की, जहां उन्होंने तालिबान को देश में 'एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक ताकत' के रूप में मान्यता दी, जिससे अफगानिस्तान की शांति, सुलह और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।[98] मेजबान तालिबान से यह आश्वासन भी प्राप्त करने में सफल रहे कि चीन की सुरक्षा चिंताओं का समाधान किया जाएगा।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद, चीन पहला देश था जिसने अफगानिस्तान को आपातकालीन मानवीय सहायता (31 मिलियन डॉलर) देने का वचन दिया था।[99] तालिबान शासन, जो मानवीय तबाही और आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, ने बीजिंग द्वारा खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की शीघ्र डिलीवरी का स्वागत किया और इसने दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए मंच तैयार किया।

मार्च 2022 में, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अफ़गानिस्तान का अचानक दौरा किया और काबुल में अपने अफ़गान समकक्ष से

मुलाकात की।[100]

"China says Taliban expected to play 'important' Afghan peace role" Reuters, July 29, 2021. Available at: https://www.reuters.com/world/china/taliban-delegation-visits-china-taliban-spokesperson-2021-07-28/#:~:text=Nine%20Taliban%20representatives%20met%20Foreign,discussed%2C%20a%20Taliban%20spokesperson%20said.

98 "China offers $31m in emergency aid to Afghanistan". BBC, September 9, 2021. Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58496867(Accessed on 9.4.2022))

99 China's foreign minister makes surprise Afghanistan trip. Deutsche Welle, March 24, 2022. Available at: https://www.dw.com/en/chinas-foreign-minister-makes-surprise-afghanistan-trip/a-61249265 (Accessed on 9.4.2022)

बीजिंग ने तालिबान को 31 मार्च, 2022 को टुन्क्सी शहर में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के बीच तीसरे विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रतिनिधि भेजने के लिए भी आमंत्रित किया और यह पहली बार था जब तालिबान का कोई अधिकारी चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की बैठक में शामिल हुआ।[101] इस वार्ता का पहला अध्याय सितंबर 2021 में इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था, तालिबान द्वारा अशरफ गनी शासन से सत्ता हथियाने के तुरंत बाद, जबकि ईरान ने अक्टूबर के अंत में तेहरान में दूसरी बैठक की मेजबानी की, जिसमें तालिबान ने भाग नहीं लिया।

चीन सितंबर 2023 में अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बन गया, जिससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या ये घटनाक्रम अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने के लिए चीन की तत्परता का संकेत देते हैं। हालाँकि, उस समय, बीजिंग ने यह कहकर शासन की औपचारिक मान्यता की उम्मीदों को कम करने का फैसला किया कि तालिबान को पूर्ण राजनयिक मान्यता के लिए विचार किए जाने हेतु राजनीतिक सुधार शुरू करने, सुरक्षा में सुधार करने और अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने की आवश्यकता होगी।[102] चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा,

'चीन का मानना है कि अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए' और 'विभिन्न पक्षों की चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान किए जाने पर अफगान सरकार को राजनयिक मान्यता स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी।'[103] जनवरी **2024** में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करते समय तालिबान द्वारा आमंत्रित किये जाने वाले **11** क्षेत्रीय और पड़ोसी

100 "China holds multinational meetings to discuss Afghanistan." Al Jazeera, March 30, 2022. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2022/3/30/china-holds-multinational-meetings-to-discuss-afghanistan (Accessed on 9.4.2022)

101 "China became the first country to host Taliban Ambassador". ICWA Viewpoint, December 14, 2024. Available at: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=10268&lid=6538(Accessed on 30.1.24)

102 "China seeks a more 'inclusive' Taliban". Radio Free Asia, December 5, 2023. Available at: https://www.rfa.org/english/news/china/afghanistan-taliban-ambassador-**12052023145223.html**

चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने 'जल्दबाजी में' अपने सभी सैनिकों को देश से वापस बुलाकर सुरक्षा स्थिति को बिगड़ने दिया और अफगान लोगों के लिए 'गड़बड़ी और अशांति' छोड़ दी।

देशों में चीन भी शामिल था। [104] इसके तुरंत बाद, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्यूबा, पाकिस्तान, ईरान और 38 अन्य देशों के राजदूतों के साथ एक औपचारिक समारोह में तालिबान शासित अफगानिस्तान के चीन में राजदूत के रूप में बिलाल करीमी के परिचय पत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया।[105]

कूटनीतिक मोर्चे पर, चीन ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहायता जुटाने के प्रयास किए हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंध हटाने और अफगान विदेशी परिसंपत्तियों पर लगी रोक हटाने का आह्वान किया है। इसी प्रकार, बीजिंग और पाकिस्तान ने मिलकर पश्चिमी शक्तियों से तालिबान से बातचीत करने और देश को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। तालिबान शासन को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय

वैधता प्राप्त करने के लिए बीजिंग का समर्थन महत्वपूर्ण है और इसलिए उसने चीनी चिंताओं को समायोजित करने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट [106] में कहते हुए 'हाल में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि तालिबान ने देश में विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए

कदम उठाए हैं', इसमें यह संकेत दिया गया है कि तालिबान

104 "*Taliban* hosts '*Afghanistan Regional* Cooperation Initiative' *Meeting* in Kabul" ICWA View Point, January 31, 2024. Available at: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=10456&lid=6670.

105 "China's President Receives Afghan Ambassador; Taliban Seek Recognition From Russia, Iran." Voice of America, Jan 30, 2024. Available at: https://www.voanews.com/a/china-s-president-receives-afghan-ambassador-taliban-seek-recognition-from-russia-iran-/7463837.html (Accessed on 31.1.24)

106 Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council. Feb 3, 2022. Available at: https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/416/14/PDF/N2141614.pdf?OpenElement (Accessed on 12.4.2022)

एक ऐसे समूह पर परिचालन प्रतिबंध लगा रहा है जो चीन के लिए विशेष रुचि रखता है, जैसे तुर्केस्तान इस्लामिक पार्टी (टीआईपी) या ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम)। वहीं, चीन ने तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ अपनी आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी जारी रखी है तथा उसकी हानिकारक घरेलू नीतियों पर काफी हद तक चुप्पी बनाए रखी है। चीन ने लगातार अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और निर्णय लेने में उसकी स्वायत्तता के प्रति सम्मान की पुष्टि की है। इसके अलावा, चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने 'जल्दबाजी में' अपने सभी सैनिकों को देश से वापस बुलाकर सुरक्षा स्थिति को बिगड़ने दिया और अफगान लोगों के लिए 'गड़बड़ी और अशांति' छोड़ दी।[107] उसका मानना है कि अफगानिस्तान की गंभीर स्थिति से निपटना अमेरिका की जिम्मेदारी और दायित्व है। बीजिंग ने राष्ट्रपति बाइडेन के 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (9 बिलियन से अधिक जमी हुई अफगान संपत्तियों में से) को मुक्त करने और उस धन को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और 9/11 के पीड़ितों के लिए एक कोष के बीच विभाजित करने के कार्यकारी आदेश की कड़ी आलोचना की। पिछली सरकार को अमेरिकी समर्थन और अमेरिका-तालिबान युद्ध में हार के

बावजूद, चीन इस क्षेत्र में अमेरिका के निरंतर प्रभाव को लेकर चिंतित है। जब भी तालिबान-अमेरिका सहयोग की खबरें सामने आई हैं, खासकर खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में, चीन चिंतित हो गया है। अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद, कुछ क्षेत्रों में ऐसी उम्मीदें थीं कि चीन आगे आएगा और सुरक्षा, आर्थिक, कूटनीतिक और मानवीय शून्य को भरेगा। हालाँकि, इस तरह की सक्रिय भागीदारी अनुपस्थित रही है। अफ़गानिस्तान में चीन की मौजूदगी अपेक्षाकृत कम है, और

107 "China blames US for Afghan crisis." The Hindustan Times, September 2021. Available at: https://www.hindustantimes.com/world-news/china-blames-us-for-afghan-crisis-101626030047818.html

अगस्त 2021 के बाद शासन के साथ जुड़ाव के प्रक्षेपवक्र के आधार पर, यह तर्क दिया जा सकता है कि अफ़गानिस्तान में चीन की रणनीति अफ़गानिस्तान में उसके दोहरे हितों से निर्देशित है।

1. सुरक्षा व्यवस्था

अप्रैल 2023 में, चीन ने अफगानिस्तान पर अपना 11-सूत्रीय स्थिति पत्र जारी किया, जिसमें संकटग्रस्त देश के प्रति बीजिंग की नीति और आगे चलकर तालिबान के साथ अपने जुड़ाव में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका स्पष्ट संकेत दिया गया।[108] बीजिंग के लिए, तालिबान के साथ संबंधों में सुरक्षा एक प्राथमिकता बनी हुई है। वह यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि अफगानिस्तान ईटीआईएम जैसे आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने, जो एक उइगर समूह है जिसे बीजिंग अपने पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में अशांति के लिए जिम्मेदार मानता है। कुछ विश्लेषकों ने 13 सितम्बर को नवनियुक्त राजदूत के साथ चीनी सैन्य अताशे की

उपस्थिति को दोनों देशों के बीच संबंधों में व्याप्त प्राथमिकता वाली सुरक्षा संबंधी चिंताओं का संकेत माना है।[109] हालाँकि, इस बात पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं कि वर्तमान में ईटीआईएम अफगानिस्तान से चीन के लिए किस हद तक सीधा खतरा पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक

रिपोर्ट बताती है कि ईटीआईएम के सदस्यों (केवल कुछ सौ व्यक्ति) को तालिबान द्वारा सीमावर्ती बदख्शां क्षेत्र से देश के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो चीन के खिलाफ उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने का एक प्रयास प्रतीत होता है।[110]

108 "China's Position on the Afghan Issue". Ministry of Foreign Affairs, People's Republic of China, April 12, 2023. Available at: https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202304/t20230412_11057785.html (Accessed on 18.9.23_)

109 "China Appoints First Ambassador to Afghanistan Since Taliban Return." Voice of America, Sep 13, 2023. Available at: https://www.voanews.com/a/china-appoints-ambassador-to-afghanistan-for-first-time-since-taliban-s-return/7266961.html (Accessed on 18.9.23)

110 United Nations, Security Council, 'Twenty-ninth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals and entities', S/2022/83, February 3, 2022, pp. 16–17.

**चीन के आर्थिक हित विविध हैं,
जिनमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं
से लेकर खनन और ऊर्जा विकास तक शामिल हैं।**

हालांकि, चीन की चिंताओं में यह भी शामिल है कि अफगानिस्तान का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए आधार के रूप में किया जा रहा है, जिसका असर मध्य और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी फैल सकता है, जहाँ निवेश और चीनी नागरिकों की संख्या के संदर्भ में चीनी उपस्थिति काफी अधिक है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले से ऐसी चिंताएं और बढ़ जाती हैं।[111]

1. आर्थिक पहलू

चीन के आर्थिक हित विविध हैं, जिनमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लेकर खनन और ऊर्जा विकास तक शामिल हैं। चीन ने अफ़गानिस्तान के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करने में अपनी रुचि व्यक्त की है, जिसका कुल मूल्य लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इन संसाधनों में तांबा, लिथियम और सोने के पर्याप्त भंडार शामिल हैं।[112] अप्रैल 2022 में, तालिबान ने काबुल के बाहर एक औद्योगिक पार्क के लिए 216 मिलियन डॉलर की चीनी निवेश परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें 150 कारखानों की मेजबानी करने की उम्मीद है।[113] Reportedly, in 2023, Chinese telecom giant

111 Delaney, R., 'China faces an increase in extremist threats in Central Asia, US panel is told', South China Morning Post, May 13, 2022. Available at: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/

article/3177557/china-faces-increase-extremist-threats-central-asia-us-panel. (Accessed on 18.9.23)

112 "China Eyes Afghanistan's $1 Trillion of Minerals with Risky bet on Taliban". Bloomberg, August 24, 2021. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-24/china-s-eyes-1-trillion-of-minerals-with-risky-bet-on-taliban (Accessed on 19.9.23_)

113 'Chinese businesses make headway in Afghanistan despite Beijing's cautious approach to Taliban', South China Morning Post, August 28, 2022. Available at: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3190469/chinese-businesses-make-headway-afghanistan-despite-beijings. (Accessed on 19.9.23_)

जब संयुक्त राज्य अमेरिका तालिबान के साथ
शांति समझौते पर बातचीत कर रहा था,
तो भारत इस व्यवस्था को लेकर आशंकित था,
उसे एक ऐसे समूह की वापसी की चिंता थी,
जिसके सहयोगियों ने काबुल में भारतीय दूतावास
और अफगानिस्तान में अन्य स्थानों पर
देश के वाणिज्य दूतावासों को
बार-बार निशाना बनाया था।

कथित तौर पर, 2023 में, चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के शीर्ष स्तरों से प्रांतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी मिल गई है, जिससे चिंता बढ़ गई है कि बीजिंग देश में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अफगानों की प्रोफाइलिंग की ओर बढ़ रहा है।[114] उस वर्ष के आरंभ में, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बीजिंग द्वारा समर्थित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर एक समझौता किया था।[115] उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान उस क्षेत्र में केन्द्रीय स्थान रखता है जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड अवसंरचना पहल के लिए अर्थपूर्ण महत्व रखता है। एक-दूसरे के दूतों की मेजबानी करना एक तरह से चीन और तालिबान दोनों की एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा का संकेत है।

भारत की अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है"[116] और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर अपने पड़ोसी के साथ उसके मजबूत संबंध रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक अफगान सरकारों के साथ विशेष रूप से

114 "Is Profiling China's New Game Plan in Afghanistan? Huawei to Install CCTVs in All Provinces." News 18, August 18, 2023. Available at: https://www.news18.com/world/is-profiling-chinas-new-game-plan-in-afghanistan-huawei-to-install-cctvs-in-all-provinces-exclusive-8540583.html. (Accessed on 19.9.23_)

115 "China and Pakistan agree to extend Belt and Road Initiative to Afghanistan."WION, May 7, 2023. Available at: https://www.wionews.com/south-asia/china-and-pakistan-agree-to-extend-belt-and-road-initiative-to-afghanistan-590042. (Accessed on 19.9.23_)

116 " India's International Land border". The Ministry of Home Affairs, Government of India. Available at: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/BMIntro-1011.pdf

2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से, तालिबान शासित अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति अफगान लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने जैसे कारकों द्वारा आकार ले रही है और इस संदर्भ में उस उद्देश्य की दिशा में वृद्धिशील कदम उठा रही है।

घनिष्ठ संबंध थे और उसने 2001 के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत अफगान गणराज्य को सहायता और सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक था, जिसने 2002 और 2021 के बीच करीब 3 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका तालिबान के साथ शांति समझौते पर बातचीत कर रहा था, तो भारत इस व्यवस्था को लेकर आशंकित था, उसे एक ऐसे समूह की वापसी की चिंता थी, जिसके सहयोगियों ने काबुल में भारतीय दूतावास और अफगानिस्तान में अन्य स्थानों पर देश के वाणिज्य दूतावासों को बार-बार निशाना बनाया था। इनमें से सबसे भयानक हमला 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुआ था, जिसमें 58 लोग मारे गए थे।[117] अन्य क्षेत्रीय देशों के विपरीत, भारत ने 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के एक बार फिर से सत्ता पर कब्जा करने से पहले तालिबान के साथ बातचीत करने से परहेज किया।

यूएनएससी प्रस्ताव 2593 को भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी द्वारा 30 अगस्त, 2021 को पारित किया गया, जिसमें रूस और चीन ने मतदान से परहेज किया।[118] प्रस्ताव में मांग की गई कि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को धमकाने या हमला करने, आतंकवादियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने, या आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने या उन्हें वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराते हुए,

117 "Indian embassy in Afghan capital attacked again." Reuters, October 9, 2009. Available at: https://www.reuters.com/article/idUSTRE59761X/

118 "UNSC 2593 is mantra for delisting Taliban shadowy leaders." Hindustan Times, September 11, 2021. Available at: https://www.hindustantimes.com/world-news/unsc-2593-is-mantra-for-delisting-taliban-shadowy-leaders-101631332467958.html

तालिबान के लिए, उनकी वैचारिक कठोरता के बावजूद, विकास सहायता की सख्त जरूरत है और शासन की स्थिरता की खोज क्षेत्रीय देशों के साथ जुड़ाव की मांग करती है।

प्रस्ताव में यूएनएससी प्रस्ताव 1267, यानी लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद (1999) द्वारा नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का भी आह्वान किया गया।[19] दोनों पक्षों के बीच पहली सार्वजनिक बातचीत 31 अगस्त, 2021 को हुई, जब कतर में भारतीय राजदूत ने तालिबान पक्ष के अनुरोध पर दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई से मुलाकात की।[20] इसके बाद 19 अक्टूबर, 2021 को मास्को में अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप वार्ता के दौरान तालिबान प्रतिनिधियों के साथ विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई।[21] भारत ने बार-बार दोहराया है कि अफगानिस्तान के प्रति उसका दृष्टिकोण अफगानिस्तान के लोगों और उनकी भलाई पर केंद्रित है।

2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से, तालिबान शासित अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति अफगान लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने जैसे कारकों द्वारा आकार ले रही है और इस संदर्भ में उस उद्देश्य की दिशा में वृद्धिशील कदम उठा रही है। भारत को शायद यह अहसास

हो गया है कि उसकी रणनीतिक दूरी उसके अपने हितों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जब चीन, पाकिस्तान, ईरान और चार मध्य एशियाई राज्यों सहित अफगानिस्तान के अधिकांश पड़ोसी देश तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से भारत

119 Ibid

120 "Meeting in Doha". Ministry of External Affairs, Govt. of India, August 31, 2021. Available at: https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/34208/Meeting_in_Doha#:~:text=Today%2C%20Ambassador%20of%20India%20to,request%20of%20the%20Taliban%20side.

121 "Indian Delegation Meets Taliban Team on Sidelines of Moscow Format Meet on Afghanistan," India Today, October 21, 2021, https://www.indiatoday.in/india/story/taliban-delegation-meets-indian-official-on-sidelines-of-moscow-format-afghanistan-talks-in-russia-1867249-2021-10-20.

को अपने रणनीतिक उद्देश्य को हासिल करने की संभावना की कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत के लिए, यह उचित ही है कि वह कूटनीतिक आदान-प्रदान और विकासात्मक सहायता के रूप में तालिबान को अफगान धरती से आतंकवाद के निर्यात की अनुमति न देने के लिए कुछ कारण बताने का प्रयास करे।[122] तालिबान के लिए, उनकी वैचारिक कठोरता के बावजूद, विकास सहायता की सख्त जरूरत है और शासन की स्थिरता की खोज क्षेत्रीय देशों के साथ जुड़ाव की माँग करती है। जून 2022 में, नई दिल्ली ने तालिबान के अधिग्रहण के बाद पहली बार अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए काबुल में भारतीय दूतावास में एक 'तकनीकी टीम' तैनात करने का फैसला किया।[123]

2021 के बाद, अफगानिस्तान में भारत के प्रयास मानवीय सहायता के साथ-साथ दवाओं, टीकों और भोजन के माध्यम से लोगों की सहायता करने पर केंद्रित रहे हैं। अफगानिस्तान में मानवीय संकट को टालने के लिए, भारत ने फरवरी 2022 में पाकिस्तान के माध्यम से 40,000 मीट्रिक टन (एमटी)[124] गेहूं और मार्च 2023 में ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अतिरिक्त 20,000 मीट्रिक टन गेहूं[125] की आपूर्ति की, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के माध्यम से वितरित किया जाएगा। साथ ही, अक्टूबर 2022 में 45 टन

चिकित्सा सहायता भी भेजी जाएगी, जिसमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, टीबी रोधी दवाएं, कोविड-19 टीकों की 500,000 खुराकें, सर्दियों के कपड़े और आपदा राहत सामग्री के टन सहित अन्य आपूर्ति शामिल

122 "India-Taliban Relations: A Careful balancing act driven by pragmatism". Middle East Institute, May 30, 2023. Available at: https://www.mei.edu/publications/india-taliban-relations-careful-balancing-act-driven-pragmatism

123 "India re-establishes diplomatic presence in Afghanistan, deploys technical team" The Hindustan Times, June 24, 2022. Available at: https://www.hindustantimes.com/india-news/india-re-establishes-diplomatic-presence-in-afghanistan-deploys-technical-team-101656001272895.html

124 "India Makes New Commitment to Supply 20,000 MT of Wheat to Afghanistan." The Wire, March 7, 2023. Available at: https://thewire.in/diplomacy/india-afghanistan-wheat-supply-new-commitment

125 "In a first since Taliban takeover, India to deliver aid to Afghanistan via Chabahar port." Wion, March 7, 2023. Available at: https://www.wionews.com/india-news/in-a-first-since-taliban-takeover-india-to-deliver-aid-to-afghanistan-via-chabahar-port-569704

हैं।[126] इसके अलावा, भारत के 2023-2024 और 2024-2025 के केंद्रीय बजट में भी अफगानिस्तान के लिए 25 मिलियन डॉलर के विकास सहायता पैकेज का विशेष प्रावधान किया गया है, जिसका तालिबान ने स्वागत किया है।[127] तालिबान ने भारत से अनुरोध किया है कि वह देश भर में लगभग 20 अधूरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को पूरा करे।[128] सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली को वीज़ा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद, भारत सरकार ने अफगानों के लिए एक नई आपातकालीन ई-वीजा श्रेणी की घोषणा की। भारतीय ई-वीज़ा की मांग तब और बढ़ गई जब भारत ने 15 अगस्त, 2021 से पहले दिए गए सभी अप्रयुक्त वीज़ा रद्द कर दिए और इसके परिणामस्वरूप भारत की साख को भारी नुकसान हुआ।

ऐतिहासिक रूप से, भारत-अफगान संबंध लोगों के बीच आपसी संपर्क पर केन्द्रित रहे हैं, चाहे सत्ता में कोई भी हो। अफगानिस्तान से आने वाले छात्रों के लिए भारत सबसे अनुकूल गंतव्य रहा है, पिछले 16 वर्षों में 60,000 से अधिक अफगान छात्रों ने भारत में अपनी पढ़ाई पूरी की है।[129] भारत द्वारा 2022 में अफगानिस्तान में अपनी आधिकारिक टीम भेजने के तुरंत बाद, ऐसी रिपोर्टें आईं कि तालिबान भारत में अपने सैन्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण चाहता था।[130] काबुल में तालिबान के बाद की स्थिति में,

126 "India Delivers fresh Batch of medical supplies to Afghanistan". Mint.com, October 11, 2022. Available at: https://www.livemint.com/news/world/india-delivers-fresh-batch-of-medical-supplies-to-afghanistan-11665476982780.html

127 "Afghan Taliban Government welcomes budget". The Economic Times, February 3, 2023. Available at: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/afghan-taliban-government-welcomes-budget/articleshow/97561107.cms

128 "India May Restart 20 Stalled Projects In Afghanistan, Says Taliban: Report". NDTV, December 1, 2022. Available at: https://www.ndtv.com/india-news/india-may-restart-20-projects-in-afghanistan-taliban-3567520

129 "Can't return to Taliban, can't stay in uncertainty in India—Afghan students' woes only rise". The Print, August 18, 2022. Available at: https://theprint.in/feature/cant-return-to-taliban-cant-stay-in-uncertainty-in-india-afghan-students-woes-only-rise/1087581/

130 "Taliban want army training in India". The Indian Express, June 11, 2022. Available at: https://www.newindianexpress.com/nation/2022/Jun/11/taliban-want-army-training-in-india-2464223.html

अफगानिस्तान में वर्तमान सुरक्षा स्थिति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, और वह तालिबान के नेतृत्व वाले शासन के तहत अफगानिस्तान से भारत के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी आतंकवादी खतरे को रोकना चाहता है।

अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली ने शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2024 तक ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अफगान नागरिकों को सालाना 1000 आईसीसीआर छात्रवृत्तियां प्रदान करना शुरू किया है।[131] भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत, अफगान अधिकारियों ने 2023 में आईआईएम कोझीकोड में भारतीय कानून और कारोबारी माहौल पर चार दिवसीय वर्चुअल पाठ्यक्रम में भाग लिया।[132] तालिबान ने अपने देश के पुनर्निर्माण में भारत से सहायता मांगी है। एक ऐसे शासन के लिए जो कूटनीतिक और वित्तीय रूप से अलग-थलग पड़ चुका है, भारत के साथ उसका जुड़ाव बहुत व्यावहारिक है, क्योंकि नई दिल्ली का भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है और अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशियाई बाजारों तक पहुँचने में उसकी दीर्घकालिक रुचि है। हालाँकि, उन कारकों को समझना दिलचस्प होगा जिन्होंने नई दिल्ली को अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जुड़ने के लिए

प्रेरित किया:

सुरक्षा की दृष्टि से खतरा: अफगानिस्तान में वर्तमान सुरक्षा स्थिति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, और वह तालिबान के नेतृत्व वाले शासन के तहत अफगानिस्तान से भारत के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी आतंकवादी खतरे को

रोकना चाहता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि अफगान क्षेत्र कट्टरपंथ और आतंकवाद (क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों) का स्रोत न बने।

131 Scholarships for Afghan Nationals 2023-2024. Indian Council for Cultural Relations, Govt. of India. Available at: https://iccr.gov.in/scholarships-afghan-nationals-online-courses-ay-2023-24.

132 "India is teaching the Taliban how to run an economy", Quartz, March 15, 2023. Available at: https://qz.com/india-is-teaching-the-taliban-how-to-run-an-economy-1850227155

तालिबान के प्रति क्षेत्रीय देशों की चिंताएं और
हित अलग-अलग हैं, और तालिबान शासन
के प्रति उनकी नीतिगत दृष्टिकोण
भी अलग-अलग हैं। हालांकि, एक बात स्पष्ट है
कि इन देशों का मानना है कि शासन के साथ संपर्क आवश्यक है, भले ही
संपर्क की तीव्रता अलग-अलग हो।

हथियारों की तस्करी: संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 के बाद अफगानिस्तान में 7 बिलियन डॉलर के सैन्य उपकरण छोड़े हैं, और इन हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने का खतरा भारत के लिए एक और चिंता का विषय है। 2022 में, ऐसी खबरें आईं कि नाटो बलों और आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए गए बम और हथियार जम्मू और कश्मीर में पहुंच रहे थे, जिससे यह आशंका पैदा हो गई कि वे क्षेत्र में इस्लामी विद्रोह को बढ़ावा दे सकते हैं।[133]

क्षेत्रीय स्थिरता: अफगानिस्तान की स्थिरता और देश में परम्परागत रूप से प्राप्त सद्भावना को बनाए रखने में भारत की वैध रुचि है। अफगानिस्तान भारत की महाद्वीपीय आर्थिक आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मध्य एशिया और ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध भी शामिल हैं।

उपरोक्त चर्चा से यह बात उजागर होती है कि तालिबान के प्रति क्षेत्रीय देशों की चिंताएं और हित अलग-अलग हैं, तथा तालिबान शासन के प्रति उनकी नीतिगत दृष्टिकोण भी अलग-अलग हैं। हालांकि, एक बात स्पष्ट है कि ये देश मानते हैं कि शासन के साथ संपर्क आवश्यक है, भले ही संपर्क की तीव्रता

अलग-अलग हो। विगत वर्षों से यह संकेत मिलता है कि काबुल और उसके क्षेत्रीय साझेदार आपसी सरोकार के मुद्दों के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण कार्य-प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को रोकना, व्यापार को बढ़ावा देना तथा जल एवं सीमा विवादों का प्रबंधन करना शामिल है।

133 "How NATO weapons affect Kashmir militancy". DW, May 18, 2022. Available at: https://www.dw.com/en/how-nato-weapons-from-afghanistan-are-impacting-kashmirs-militancy/a-61838513

कई लोगों का मानना था कि ये प्रारंभिक वादे
न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह आभास
देने के लिए किए गए थे कि वर्तमान शासन
अपने पिछले अवतार से भिन्न होगा,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने
का मामला भी बनाने के लिए किए गए थे।

निम्नलिखित अनुभाग काबुल के अपने निकटतम पड़ोस के प्रति दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, तथा इस प्रक्रिया में, कुछ ऐसे कारकों पर चर्चा करता है, जिन्होंने तालिबान के दृष्टिकोण के निर्माण को प्रभावित किया हो सकता है।

क्षेत्र पर तालिबान का जोर

15 अगस्त, 2021 को अफ़गानिस्तान की राजधानी पर कब्ज़ा करने के बाद, तालिबान ने देश भर में महिलाओं के अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता और सरकारी अधिकारियों के लिए 'माफ़ी' का वादा किया था।[134] 17 अगस्त को अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आश्वासन दिया कि तालिबान कोई बदला नहीं लेना चाहता और 'सभी को माफ कर दिया गया है।'[135] एक 'समावेशी' सरकार के बारे में भी बातचीत हुई, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि तालिबान ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि वह पहले ही 'विजयी' पक्ष के रूप में उभरा है। कई लोगों का मानना है कि ये शुरुआती वादे

न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह आभास देने के लिए किए गए थे कि वर्तमान शासन अपने पिछले अवतार से अलग होगा,

बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए भी एक मामला बनाने के लिए किए गए थे। हालाँकि, एक भी विदेशी सरकार या बहुपक्षीय संगठन ने औपचारिक रूप से तालिबान-नियंत्रित सरकार को स्वीकार नहीं किया। वर्दी पहनने से इनकार करने से

134 "Taliban offers amnesty, promises women's rights and media freedom." Al Jazeera, August 17, 2021. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/evacuation-flights-resume-as-biden-defends-afghanistan-pullout

135 "Taliban Declares complete amnesty across Afghanistan. "The Economic Times, August 18, 2021. Available at: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/taliban-declares-complete-amnesty-across-afghanistan-says-everyone-is-forgiven/articleshow/85418061.cms?from=mdr (Accessed on 3.8.2022)

जब से तालिबान सत्ता में लौटा है,
तालिबान
नेतृत्व के भीतर गुटबाजी
की अटकलें सुर्खियों में हैं।

तालिबान के अधिक रूढ़िवादी तत्व नाराज हो गए, जिससे आंदोलन दो खेमों में बंट गया: एक, काबुल स्थित अंतरिम सरकार, जो पश्चिम के साथ संबंधों में मधुरता लाना चाहती थी; और दूसरी, कट्टरपंथी अमीर हिबतुल्लाह अखुंदजादा के कंधार मुख्यालय के आसपास एकत्रित हुई, जिसने इस धारणा को खारिज कर दिया।[136] अमीर के खेमे को यह विश्वास हो गया कि तालिबान को अपने आंदोलन की एकजुटता और शासन के अस्तित्व की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए 1990 के दशक में उनके पिछले शासन द्वारा निर्धारित सख्त नीतियों को फिर से लागू करना चाहिए।[137] 2022 और 2023 में महिलाओं के अधिकारों पर कठोर आदेशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए,[138] अमीर ने पश्चिम के प्रति अपनी अवज्ञा प्रदर्शित की तथा अपने अनुयायियों को आश्वस्त किया कि तालिबान शासन समझौता नहीं करेगा।

जब से तालिबान सत्ता में लौटा है, तालिबान नेतृत्व के भीतर गुटबाजी की अटकलें सुर्खियों में हैं। शुरुआती दिनों में कहा गया कि तालिबान आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से पश्तून शामिल हैं, जातीय, क्षेत्रीय और जनजातीय आधार पर विभाजित है; बाद के दौर में नीतिगत मुद्दों पर मतभेदों की बात की जाने लगी। 2022 के मध्य में, तालिबान के वरिष्ठ

नेताओं ने एक-दूसरे की दुर्लभ सार्वजनिक आलोचना की थी, जिससे इस बात पर आंतरिक मतभेद की अटकलें फिर से शुरू हो गई थीं कि क्या लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

136 "The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy and Afghanistan." International Crisis Group, January 30, 2024. Available at: https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/337-talibans-neighbourhood-regional-diplomacy-afghanistan#_ftn3

137 Ibid

138 "Taliban's restriction of women's rights deepen Afghanistan Crisis". International Crisis Group, February 23, 2023. Available at: https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/329-taliban-restrictions-womens-rights-deepen-afghanistans-crisis

तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई ने लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय में जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तालिबान नेतृत्व की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए कहा, 'हमें अपने लोगों पर डंडों से शासन करने के बजाय उनके दिलों को जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए।'[139] अगले वर्ष, तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने सत्ता पर 'एकाधिकार' करने के लिए नेतृत्व के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि तालिबान प्रशासन को ऐसी नीतियों को अपनाने से बचना चाहिए जो '[सत्तारूढ़] प्रणाली और लोगों के बीच दरार पैदा करें, तथा दूसरों को इस्लाम को बदनाम करने के लिए इसका फायदा उठाने का मौका दें।'[140] हक्कानी की टिप्पणी तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा पर लक्षित प्रतीत हुई। प्रख्यात अफगानिस्तान विशेषज्ञ एंटोनियो गुस्तोजी ने तर्क दिया है कि तालिबान द्वारा लड़कियों की शिक्षा को निलंबित करने का कदम संभवतः अमीर द्वारा काबुल में कैबिनेट के सदस्यों द्वारा पश्चिमी देशों के साथ बातचीत करने के प्रयासों को विफल करने के लिए उठाया गया है।[141] इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2023 और 2024 में कतर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलनों से तालिबान अनुपस्थित रहा, जहाँ लैंगिक प्रश्न ही बातचीत का मुख्य विषय रहा। तालिबान की लचीलेपन की कमी, विशेषकर लैंगिक नीतियों के मामले में, के कारण संबंध और भी खराब हो गए तथा पश्चिम के साथ राजनयिक गुंजाइश और भी

कम हो गई। विद्वानों का तर्क है कि जैसे ही तालिबान ने पश्चिम पर विजय पाने की उम्मीद छोड़ दी, उसका दृष्टिकोण क्षेत्र की ओर बदल गया।[142]

139 "Unprecedented Differences': Rifts Within The Taliban Come Out In The Open." Radio Free Europe, June 2, 2022. Available at: https://www.rferl.org/a/taliban-rifts-exposed-afghanistan/31880018.html

140 "Top Taliban Official's Public Criticism Reignites Internal Rift Speculations". VOA, February 13, 2023. Available at: https://www.voanews.com/a/top-taliban-official-s-public-criticism-reignites-internal-rift-speculations-/6961488.html

141 Antonio Guustozzi, "China's Current Stakes in Afghanistan". ORF Special Report, No. 233. 2024, pp. 11-16.

142 "The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy and Afghanistan." International Crisis Group, Jan 30, 2024. Available at: https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/337-talibans-neighbourhood-regional-diplomacy-afghanistan#_ftn3

तालिबान ने इस क्षेत्र और इसके बाहर सकारात्मक संबंध बनाने पर जोर दिया। फिर भी, ऐसे बयानों के साथ अक्सर यह दावा भी किया जाता है कि, जैसे तालिबान विदेशी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, वैसे ही अन्य देशों को भी अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।[143] ऐसे समय में जब अफगानिस्तान आर्थिक गतिरोध और राष्ट्रव्यापी मानवीय संकट का सामना कर रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा अफगानिस्तान में मानवीय राहत के लिए और 11 सितंबर, 2001 के हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए जब्त की गई अफगान संपतियों में से 7 बिलियन डॉलर को विभाजित करने के निर्णय ने दोनों पक्षों के बीच मामलों को और जटिल बना दिया।[144] तालिबान के अधिकारी भी वाशिंगटन के प्रति अपने असंतोष के बारे में अधिक मुखर हो गए हैं, यही भावना चीन, ईरान और रूस जैसे क्षेत्रीय ताकतों द्वारा भी दोहराई गई है, जिनके पास अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था के विकल्प तलाशने के अपने कारण हैं। हालांकि, पड़ोसी देशों द्वारा काबुल के प्रति सतर्कतापूर्ण रवैया मुख्य रूप से अमेरिका विरोधी भावना पर आधारित नहीं है, बल्कि इस आकलन पर आधारित है कि इससे उनकी सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं के संबंध में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कथित तौर पर, एक क्षेत्रीय राजनयिक ने कहा, 'दुनिया रुककर पश्चिमी भावनाओं के तालिबान के पक्ष में जाने का इंतजार नहीं करेगी...हम यहां अग्रिम पंक्ति में हैं।[145]

तालिबान ने अपनी ओर से 29 जनवरी, 2024 को काबुल में 'अफगानिस्तान

क्षेत्रीय सहयोग पहल' शीर्षक से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की।

143 "International community should stop meddling in Afghan affairs: Taliban". Business Standard, April 4, 2024. Available at: https://www.business-standard.com/article/international/international-community-should-stop-meddling-in-afghan-affairs-taliban-122050200180_1.html

144 "Taliban reacts to US plan on frozen assets, says funds belongs to Afghans" Business Standard, February 14, 2022. Available at: https://www.business-standard.com/article/international/taliban-reacts-to-us-plan-on-frozen-assets-says-funds-belongs-to-afghans-122021400093_1.html

145 "Why has China recognised Taliban's envoy to Beijing?" Al Jazeera, February 14, 2024. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2024/2/14/is-chinas-recognition-of-afghanistan-envoy-a-diplomatic-win-for-taliban

अफगान मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में चर्चा के प्रमुख विषयों में क्षेत्रीय देशों और तालिबान सरकार के बीच सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग में समन्वय बढ़ाना, एकीकृत क्षेत्रीय कथानक विकसित करना और क्षेत्र में आर्थिक अवसरों का दोहन करने के लिए सहयोग करना शामिल था। भाग लेने वाले देशों में भारत, कजाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया और किर्गिस्तान शामिल थे।[147] बैठक में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ अधिकारियों के लिए 'क्षेत्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है'।[148] तालिबान विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार,[149] मुत्ताकी ने कहा कि क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग 'सामान्य क्षेत्रीय लाभों के आधार पर क्षेत्र-केंद्रित और जुड़ाव के रास्ते तलाशने, क्षेत्र में मौजूदा और संभावित खतरों से निपटने के लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ सकारात्मक और रचनात्मक जुड़ाव के लिए क्षेत्र-केंद्रित आख्यान तैयार करने' पर केंद्रित हो सकता है।

अफगानिस्तान में शासन परिवर्तन के तीन वर्ष से अधिक समय बाद भी, देश के भीतर स्थिति निरंतर विकसित हो रही है, और इसके परिणामस्वरूप, इसके निकटतम पड़ोसी देश अफगानिस्तान की बदलती वास्तविकताओं से निपट रहे हैं।

146 Ibid

147 "Afghanistan's Taliban Host Multilateral Huddle To Promote Regional Cooperation" Voice of America. January 29, 2024. Available at: https://www.voanews.com/a/afghanistan-s-taliban-host-multilateral-huddle-to-promote-regional-cooperation/7461769.html. (Accessed on 30.1.24)

148 "*Afghanistan Regional* Cooperation Initiative Meeting held in Kabul".Islamic Emirate of Afghanistan: The Afghan Official Voice, January 29, 2024. Available at: https://www.alemarahenglish.af/afghanistans-regional-cooperation-initiative-meeting-held-in-kabul/ (Accessed on 30.1.24)

149 "*Afghanistan Regional* Cooperation Initiative Meeting held in Kabul".Islamic Emirate of Afghanistan: The Afghan Official Voice, 29 Jan, 2024. Available at: https://www.alemarahenglish.af/afghanistans-regional-cooperation-initiative-meeting-held-in-kabul/ (Accessed on 30.1.24)

उन्होंने क्षेत्र के देशों के साथ सकारात्मक बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया और राजनयिकों से तालिबान के 'क्षेत्र-उन्मुख पहल' के संदेश को अपने देशों तक पहुंचाने को कहा ताकि अफगानिस्तान और क्षेत्र सभी के लाभ के लिए नए अवसरों का संयुक्त रूप से लाभ उठा सकें।[150]

हालांकि, मौजूदा तालिबान शासन और देश की सीमाओं पर चल रहे कूटनीतिक संकटों और सुरक्षा खतरों के संबंध में प्रत्येक पड़ोसी देश की चिंताओं और मुद्दों की प्रकृति को देखते हुए, क्षेत्रीय देश तालिबान के आह्वान पर प्रतिक्रिया देने में सतर्क रहेंगे। अफ़गानिस्तान के लिए एक व्यावहारिक विदेश नीति बनाना, अफगानिस्तान के लिए एक व्यावहारिक विदेश नीति बनाने के लिए, जो सीमा सुरक्षा, व्यापार विस्तार, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और जल विवादों को संबोधित करती हो, काबुल से राजनीतिक गहराई और कूटनीतिक दक्षता की आवश्यकता होगी। यह देखना अभी बाकी है कि आने वाले दिनों में तालिबान अपने पड़ोसियों की चिंताओं का समाधान कैसे करता है। निम्नलिखित अनुभाग में अफगानिस्तान और उसके निकटतम पड़ोसियों के लिए आगे की राह पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है तथा उन मुद्दों पर चर्चा की गई है जो निकट भविष्य में संबंधों की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के लिए आगे की राह क्या है?

अफगानिस्तान में शासन परिवर्तन के तीन वर्ष से अधिक समय बाद भी, देश के भीतर स्थिति निरंतर विकसित हो रही है, और इसके परिणामस्वरूप, इसके निकटतम पड़ोसी देश अफगानिस्तान की बदलती वास्तविकताओं से निपट रहे हैं। यह निश्चित रूप से

भविष्यवाणी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि यह गतिशील क्षेत्र क्या रुख अपनाएगा; फिर भी, पिछले वर्षों में हुए घटनाक्रमों के आधार पर, यह पत्र कुछ व्यापक मुद्दों की पहचान करता है जो अफगानिस्तान के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।

150 "India among 10 countries to participate in meeting convened by Taliban in Kabul." Hindustan Times, January 29, 2024. Available at: https://www.hindustantimes.com/india-news/india-among-10-countries-to-participate-in-meeting-convened-by-taliban-in-kabul-101706549349569.html (Accessed on 30.1.24)

31 जुलाई 2022 को कार्यवाहक
आंतरिक मंत्री द्वारा नियंत्रित काबुल स्थित
घर में अल-कायदा नेता अयमान अल-जवाहिरी
की हत्या ने पड़ोसियों के बीच सवाल
खड़ा कर दिया कि क्या तालिबान पर
भरोसा किया जा सकता है।

तालिबान का सरकार विरोधी आतंकवादी समूहों को कथित समर्थन

अफगानिस्तान के निकटतम पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सुरक्षा खतरे को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाले युग के दौरान, नियंत्रण का कार्य पश्चिमी ताकतों के जिम्मे आ गया, जिनके आतंकवाद-रोधी अभियानों (खामियों के बावजूद) से देश के पड़ोसियों को राहत मिली कि आतंकवाद के मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। तालिबान के सत्ता में वापस आने से क्षेत्रीय देशों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से गतिविधियां संचालित करने वाले अनेक अंतरराष्ट्रीय जिहादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है, तथा उन्हें तालिबान की उन पर लगाम लगाने की इच्छा और क्षमता पर संदेह है। 31 जुलाई 2022 को कार्यवाहक आंतरिक मंत्री द्वारा नियंत्रित काबुल स्थित घर में अल-कायदा नेता अयमान अल-जवाहिरी की हत्या ने पड़ोसियों के बीच सवाल खड़ा कर दिया कि क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है। अमेरिकी सेना द्वारा ज़वाहिरी को मार दिए जाने के बाद, क्षेत्र

में तालिबान द्वारा अन्य आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराए जाने के प्रति अधिक सतर्कता बढ़ गई, यहां तक कि उन पर विदेशी लड़ाकों को अफगान निवास और नागरिकता के दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी आरोप लगाया गया।[151]

151 "Taliban issues 3,000 passports to terrorists, says Tajik interior minister", *Afghanistan International*, October 19, 2022.

तालिबान ने अपनी ओर से तालिबान लड़ाकों को अफगानिस्तान से बाहर हमले करने से हतोत्साहित करने के लिए आदेश जारी किए हैं और यहां तक कि उसने टीटीपी लड़ाकों को अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों से स्थानांतरित करने की योजना भी प्रस्तावित की है, बशर्ते पाकिस्तान प्रस्तावित योजना का खर्च वहन करे।

मध्य एशियाई देश स्वाभाविक रूप से देश के उत्तर में, अपनी सीमाओं के निकट स्थित उग्रवादियों, जिनकी उनके देशों में विद्रोह भड़काने की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा होती है, पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र निगरानी दल की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय देशों का दावा है कि अफगानिस्तान में अल-कायदा, इसकी स्थानीय शाखा, भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा; जेए; कतिबा-ए इमाम बुखारी; ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट/तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी; इस्लामिक जिहाद समूह; कतिबा अल-तौहीद वाल जिहाद; आईएमयू; और अन्य को शरण मिली हुई हैं।[152] इनमें से कई छोटे समूहों में लड़ाकों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन ये समूह कितने भी छोटे क्यों न हों चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के लिए प्रमुख प्राथमिकता बने हुए हैं, क्योंकि विचाराधीन आतंकवादी प्रायः उइगर, उज्बेक, ताजिक और अन्य जातीय समूहों से संबंधित होते हैं, जिनका अपने देशों के निर्वाचन क्षेत्रों से संबंध होता है।[153]

उत्तर के उग्रवादियों की तुलना में पूर्व के उनके समकक्षों को

अधिक गंभीर अंतरराष्ट्रीय खतरे हैं। भारत, अफगानिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे दो इस्लामी समूहों की कथित रूप से निरंतर उपस्थिति से चिंतित है, जो दशकों से भारतीय धरती पर हमले करते रहे हैं। इस समय सबसे सक्रिय समूह टीटीपी है, जिसका एजेंडा पाकिस्तान केंद्रित है। टीटीपी 2021 से पहले ही आक्रामक हो गया था (जैसा कि नीचे ग्राफ 1 में दर्शाया गया है),

152 Report of the UN Analytical Support and Sanctions Monitoring Team on the Taliban", UNSC S/2023/95, February 13, 2023.

153 Report of the UN Analytical Support and Sanctions Monitoring Team on the Taliban", UNSC S/2022/419, May 26, 2022.

लेकिन तालिबान के कब्जे ने समूह को काफी हद तक प्रोत्साहित किया है, खासकर 2022 में युद्धविराम को वापस लेने के बाद। तालिबान के सत्ता में आने के दौरान जेल से भागने के कारण कई टीटीपी कैदी रिहा हो गए, जिससे लड़ाकों को अफगानिस्तान छोड़ने और पाकिस्तानी राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए अपना युद्ध फिर से शुरू करने का मौका मिल गया।[154] इस्लामाबाद ने कई रणनीति अपनाकर इस सुरक्षा खतरे को दूर करने की कोशिश की: तालिबान के साथ अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की वकालत करने के लिए राजनयिक प्रयासों को रोकना; काबुल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच 2020 के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाना, जिसमें आतंकवाद विरोधी प्रावधान शामिल थे; अस्थायी रूप से सीमा चौकियों को बंद करना; और उस सीमा पर बाड़ और अन्य अवरोधों को पूरा करने की कोशिश करना, जिसे तालिबान, पहले की अफगान सरकारों की तरह, मान्यता नहीं देता है। टीटीपी के खिलाफ तालिबान की निष्क्रियता से निराश होकर, उसने कुछ दबाव की रणनीति भी अपनाई, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर हवाई और तोपखाने हमले, अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निष्कासन का अपमान, और अफगानिस्तान के लिए जाने वाले पारगमन माल पर प्रतिबंध आदि।[155] तालिबान ने अपनी ओर से तालिबान लड़ाकों को अफगानिस्तान से बाहर हमले करने से हतोत्साहित करने के लिए आदेश जारी किए हैं और यहां तक कि अफ-पाक सीमा क्षेत्रों से टीटीपी लड़ाकों को स्थानांतरित करने की

योजना भी प्रस्तावित की है, बशर्ते पाकिस्तान प्रस्तावित योजना का खर्च वहन करे। अब तक, इनमें से किसी भी रणनीति ने वांछित परिणाम नहीं दिए हैं। अटलांटिक काउंसिल के नॉन-रेजिडेंट सीनियर फेलो जाविद अहमद ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों को निशाना बनाने वाले आतंकी समूहों को तालिबान के समर्थन के मुद्दे पर एक वेबिनार में बोलते हुए तर्क दिया कि अब तक, 'तालिबान शासन अपने वर्तमान सम्बन्ध के साथ-साथ अपने पिछले सम्बन् के मामले में भी प्राथमिकताएं रखता है, जो अभी के लिए यह सुनिश्चित करने के पक्ष में झुका हुआ है कि अफगान तालिबान के अपने पिछले सहयोगियों के साथ संबंध स्थिर और पूर्वानुमान योग्य बने

154 Samina Ahmed, "The Pakistani Taliban Test Ties between Islamabad and Kabul", Crisis Group Commentary, March 29, 2023.

155 Ibraheem Bahiss, "Pakistan's Mass Deportation of Afghans Poses Risks to Regional Stability", Crisis Group Commentary, November 13, 2023.

दशकों के युद्ध और असुरक्षा के कारण, अफ़गानिस्तान जल अवसंरचना के विकास में अपने पड़ोसियों से पीछे रह गया। इस बीच, अन्य देशों ने कृषि क्षेत्र बनाए हैं जो अफ़गानिस्तान से पानी की निर्बाध आपूर्ति पर निर्भर हैं। तालिबान अब आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और महत्वाकांक्षी जल परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है जो इस क्षेत्र में चिंताएँ बढ़ा रही हैं।

रहें... तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एक अलग मोर्चा खोलने के लिए तैयार नहीं है, जहां उन्हें पूर्व सामरिक सहयोगियों के साथ झड़पों में शामिल होना पड़े।[156] यह बहुत संभव है कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों को निशाना बनाने वाले विभिन्न आतंकवादी समूहों को तालिबान शासित अफगानिस्तान में पनाहगाहें मिलती रहेंगी, और तालिबान शासन अपने निकटतम परिधि के देशों से निपटने में उनका इस्तेमाल लाभ के रूप में कर सकता है; इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में तनाव की गुंजाइश पैदा होगी।

पानी को लेकर विवाद

वर्षों के युद्ध और अस्थिरता ने अफगानिस्तान के जल क्षेत्र को प्रभावित किया है। यद्यपि देश में जल संसाधन अपेक्षाकृत अनुकूल है तथा पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों के ऊपरी भाग में इसकी स्थिति बेहतर है, फिर भी इसके जल क्षेत्र की

दुर्दशा तथा जल संसाधन प्रबंधन में गंभीर कमियों के कारण देश जल तनाव की स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने, जहाँ 80 प्रतिशत पानी बर्फ पिघलने और ग्लेशियरों से आता है, अफगानिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील देशों में शामिल कर दिया है।

156 Javid Ahmad, Non-resident Senior Fellow, Atlantic Council speaking at " The Durand Churn: Reassessing Afghanistan-Pakistan Relations" ORF Webinar, December 18, 2023. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Xap4eNlH83A&t=355s

देश के लगभग 60 प्रतिशत परिवार अब पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि गर्म सर्दियां और तीव्र वसंत ऋतु क्रमशः सूखे और बाढ़ का कारण बन रही हैं।[157] अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से, तालिबान प्रशासन देश में बिगड़ती जल स्थिति से निपटने के लिए जल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं चला रहा है। यह देखा गया है कि जल प्रबंधन काबुल में तालिबान शासन और पड़ोसी राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गया है। पानी को लेकर तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है।

दशकों के युद्ध और असुरक्षा के कारण, अफगानिस्तान जल अवसंरचना के विकास में अपने पड़ोसियों से पीछे रह गया। इस बीच, अन्य देशों ने, जो अफगानिस्तान से मिलने वाली निर्बाध जल आपूर्ति पर निर्भर हैं, कृषि क्षेत्र विकसित किए हैं। तालिबान अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और महत्वाकांक्षी जल परियोजनाएं चला रहा है, जिससे क्षेत्र में चिंताएं बढ़ रही हैं। चूंकि अफगानिस्तान एक ऊपरी तटवर्ती राज्य है, इसलिए पड़ोसी देश अफगान बांधों और सिंचाई प्रणालियों को खतरे के रूप में देखते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान की अनेक सीमापार नदियों में से केवल एक ही जल-बंटवारे समझौते के अधीन है। बाकी सभी क्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून द्वारा शासित हैं, जो जल के 'न्यायसंगत और उचित' उपयोग की बात कहता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता कि इस वाक्यांश का क्या अर्थ है।[158] एक बार पूरा हो जाने पर, उत्तर में

कोश तेपा जल नहर परियोजना और दक्षिण में हेलमंद नदी पर बांधों से अफगानिस्तान के अपने मध्य एशियाई पड़ोसियों और यहाँ तक कि आगे ईरान तक के साथ संबंधों पर और भी अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

157 Tweet by OCHA Afghanistan, @OCHAAfg, 1:42pm, May 14, 2023. Crisis Group mapping of Afghan regions affected by floods and droughts between January 1990 and October 2022 shows that rainfall excesses and deficits have become more intense, affecting larger areas for longer periods of time. Available at: https://twitter.com/ochaafg?lang=en

158 Mohsen Nagheeby, "Anarchy and the Law of International Watercourses", Northumbria University, 2021.

तालिबान द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय रही है। अप्रैल 2024 में, क्षेत्रीय पर्यावरण निगरानी समूह (रिवर विदाउट बाउंड्रीज़) द्वारा सूचना दिए जाने से एक महीने पहले तक कोश टेपा नहर से कथित जल रिसाव के बारे में रिपोर्टें आती रहीं। उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर, समूह ने इस रिसाव के लिए नहर के डिजाइन में संरचनात्मक दोषों को जिम्मेदार ठहराया।[159] निर्माण की गुणवत्ता इस बात से भी प्रभावित हो रही है कि परियोजना कितनी तेजी क्रियान्वित की जा रही है, और ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि तालिबान इसे एक ऐसी परियोजना के रूप में देख रहा है जिसका उद्देश्य उसके कुशल शासन (इसके व्यावहारिक मूल्य के अतिरिक्त) को दर्शाना है, तथा वह अपने मीडिया आउटलेट्स पर कई प्रांतों में हो रहे निर्माण कार्यों के ड्रोन से लिए गए फुटेज दिखा रहा है। अब तक उत्तरी पड़ोसियों ने शांत कूटनीति और गैर-टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, इस उम्मीद के साथ कि यह नीति तालिबान से सहयोग प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। हालाँकि, यह मुद्दा रिश्ते में तनावपूर्ण क्षेत्र बना रहेगा। पूर्वी पड़ोसी पाकिस्तान के संबंध में, काबुल नदी पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जल विवाद भी सुलग रहा है। अब तक तो ऐसा प्रतीत होता है कि शासन ने कोश तेपा नहर और हेलमंद नदी बांधों में अधिक निवेश किया है, लेकिन काबुल नदी पर परियोजनाएं निश्चित रूप

से भविष्य के लिए उनके एजेंडे

अफगानिस्तान सात देशों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ लगभग 1500 मील लंबी डूरंड रेखा सबसे अधिक संघर्ष-ग्रस्त बनी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर कोई समझौता नहीं है।

159 "Unexplained spill fuels concern about Afghan canal project."Eurasianet, April 2, 2024. Available at: https://eurasianet.org/unexplained-spill-fuels-concern-about-afghan-canal-project

में होंगी, और आने वाले दिनों में यह इस्लामाबाद के लिए चिंता का एक वैध कारण होना चाहिए।

सीमा असुरक्षा

अफगानिस्तान सात देशों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ लगभग 1500 मील लंबी डूरंड रेखा सबसे अधिक संघर्ष-ग्रस्त बनी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर कोई समझौता नहीं है। परिणामस्वरूप, तालिबान भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाने की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। उधर, इस्लामाबाद ने तालिबान सरकार पर अपनी पश्तून पहचान की पृष्ठभूमि में टीटीपी को पनाह देने तथा सीमा के अफगान हिस्से में उन्हें पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया है। काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी से उत्साहित होकर टीटीपी ने पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान में हमले बढ़ा दिए हैं। कई तरीके अपनाए गए: टीटीपी के साथ वार्ता, घरेलू आतंकवाद-रोधी अभियान, सीमा पर बाड़ लगाना, तथा अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने जैसी दबाव की रणनीति, फिर भी कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पाकिस्तान में टीटीपी की हिंसा के जवाब में, इस्लामाबाद ने तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से दो बार अफगान क्षेत्र में हवाई हमले जैसे आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हैं। ऐसी बड़ी कार्रवाइयों के अलावा, झड़पों की कई घटनाएं

हुई हैं जिनमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और मारे गए हैं।

सीमा विवादों के कारण अफगान और पाकिस्तानी सरकारें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं और इस कारण दोनों पक्षों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। झड़पों के कारण, दोनों देशों के बीच चमन, तोरखम और स्पिन-बोल्डक जैसी महत्वपूर्ण सीमा चौकियां बंद रहीं, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पुनः खोल दिया गया। यह तथ्य कि सीमा चौकियों को लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता, इस सीमा चौकियों के घनत्व और महत्व को दर्शाता है। इसलिए

यद्यपि शरणार्थियों की संख्या में वर्षों से उतार-चढ़ाव रहा है, लेकिन वर्तमान में यूएनएचसीआर का अनुमान है कि अफगानिस्तान से 8 मिलियन से अधिक शरणार्थी विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जिससे यह एशिया में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी बन गई है, और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है।

दोनों प्रशासन, समस्याओं को बहुत अधिक बढ़ने नहीं देने के पक्ष में हैं। अल्प समय में सीमा मार्ग का खुलना तथा पाकिस्तान द्वारा सीमा विवादों पर चर्चा करने के लिए मुल्लाओं का एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान भेजने का मूल्यांकन इस संदर्भ में किया जा सकता है। जनवरी 2024 में ईरान के साथ पाकिस्तान के संक्षिप्त सीमा पार संकट के विपरीत, अफगानिस्तान के साथ सीमा पर स्थिति निरंतर बनी हुई है।[160]

यद्यपि यह घटनाएं कम ही होती हैं, लेकिन अफगानिस्तान में ईरान के साथ भी सीमा पर झड़पें हुई हैं, जो मई 2023 में अधिकतम बढ़ गई थी, जब दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गोलीबारी शुरू करने का आरोप लगाया था, जिसमें कम से कम दो ईरानी और एक अफगान गार्ड मारे गए थे।[161] सीमा पर हिंसा के बाद ईरानी अधिकारियों ने मिलक-जरंज सीमा चौकी को बंद कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्रॉसिंग थी, जिसे बाद में पुनः खोल दिया गया। झड़पों के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत और ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के बीच सीमा चौकी पर गोलीबारी ऐसे समय हुई है, जब ईरान के

राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों पर 1973 की संधि का उल्लंघन करते हुए ईरान के पूर्वी क्षेत्रों में पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है। जल विवाद स्पष्ट रूप से ईरान और अफगानिस्तान के बीच सीमा संघर्ष का कारण बन गया है, और जब तक मूल कारण का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस तरह के संघर्षों के पुनः होने और

160 "Iran is pushing Pakistan to breaking point". I-news, January 18, 2024. Available at: https://inews.co.uk/opinion/iran-pushing-pakistan-breaking-point-2861199

161 "What caused deadly Afghan-Iran border clashes? What happens next?" Al jazeera, May 30, 2023. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2023/5/30/what-caused-deadly-afghan-iran-border-clashes-what-happens-next

द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहेगी।

शरणार्थी प्रवाह

यद्यपि शरणार्थियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन वर्तमान में यूएनएचसीआर का अनुमान है कि अफगानिस्तान से 8 मिलियन से अधिक शरणार्थी विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जिससे यह एशिया में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी बन गई है, तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है।[162] अफ़गान शरणार्थियों की पाँच व्यापक लहरों की पहचान की जा सकती है

- 1979 की सौर क्रांति के बाद अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने पड़ोसी ईरान और पाकिस्तान में अफ़गान शरणार्थियों की पहली लहर को जन्म दिया। शरणार्थियों की दूसरी लहर में मुख्य रूप से सोवियत समर्थक शामिल थे, जो 1989 में सोवियत वापसी के बाद अफगानिस्तान से भाग आये थे। अफगानिस्तान से शरणार्थियों की तीसरी और चौथी लहर 1990 के दशक के प्रारम्भ और 2001 के बीच आई - संघर्ष और गृहयुद्ध की तीव्रता के कारण, जब विभिन्न मुजाहिद्दीन गुट सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और जब 1996 में तालिबान ने पहली बार सत्ता पर कब्जा किया। 2001 में तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने और

अमेरिका के नेतृत्व वाले युग की शुरुआत के बाद, आशावाद की भावना थी, लाखों अफगान शरणार्थी अफगानिस्तान लौट आए, जिससे अफगानिस्तान के हाल के इतिहास में पहली बार वापसी-प्रवास का एक पैटर्न शुरू हुआ। हालाँकि, अगले कुछ वर्षों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण कई अफगानों को अपने देश छोड़कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद अफ़गानिस्तान

162 "Afghanistan Refugee Crisis Explained", UNHCR, July 18, 2023. Available at: https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/

अफ़गान शरणार्थियों के आने और उनके निर्वासन के मुद्दे ने पाकिस्तान और ईरान के साथ संबंधों को ख़राब करने में योगदान दिया। शरणार्थियों का मुद्दा ईरान और पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंधों में एक कांटा बना रहेगा

से शरणार्थियों के प्रवाह की पाँचवीं लहर देखी गई, जिसमें अनुमानित 3.6 मिलियन अफ़गान अपनी मातृभूमि से भाग गए।[163]

पिछले कई दशकों में ईरान और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफ़गान शरणार्थी रह रहे हैं। यूएनएचसीआर के अनुसार, 2021 में तालिबान के कब्जे के समय लगभग 5.5 मिलियन अफगान शरणार्थी और शरणार्थी जैसी स्थिति वाले अफगान इन देशों में रह रहे थे।[164] इसके बाद, पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को घोषणा की कि वह अफगानों सहित सभी 'अनियंत्रित अप्रवासियों' को निर्वासित कर देगी, यदि वे 1 नवंबर तक स्वेच्छा से बाहर नहीं निकलते हैं।[165] तालिबान प्रशासन ने इन निर्णयों का कड़ा विरोध किया था, इन कदमों को 'अस्वीकार्य'

बताया था तथा मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।[166] लगभग उसी समय हेरात में 6.3 तीव्रता का भूकंप आने के बाद अफगानिस्तान में फिर से मंदी छाने लगी थी, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने देश में रह रहे अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। नवंबर 2023 तक ईरान और

पाकिस्तान

163 "Afghanistan Refugee Crisis Explained", UNHCR, July 18, 2023. Available at: https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/

164 "Afghanistan Situation" Operational Data Portal UNHCR. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/afghanistan

165 "Pakistan orders illegal immigrants, including 1.73 mln Afghans, to leave." Reuters, October 3, 2023. Available at: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-orders-all-illegal-immigrants-leave-after-suicide-bombings-2023-10-03/ (Accessed on 31. 10.23)

166 "Pakistan's plan to evict thousands of Afghans 'unacceptable', says Taliban". Al Jazeera, October 4, 2023. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2023/10/4/pakistans-plan-to-evict-thousands-of-afghans-unacceptable-says-taliban (Accessed on 31. 10.23)

द्वारा 500,000 से अधिक अफगान नागरिकों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया।[167] जून 2024 में, तालिबान प्रशासन ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान से लाखों अफगान शरणार्थियों का निष्कासन बेरोकटोक जारी है, और प्रतिदिन लगभग 2,000 लोग देश में आ रहे तालिबान आयोग के प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी, जो वापस लौटने वालों को उनके मूल अफगान जिलों में सहायता और पुनर्वास प्रदान कर रहे हैं, ने कहा कि "दोनों पड़ोसी देशों ने 2024 की शुरुआत से 400,000 से अधिक शरणार्थियों को जबरन निर्वासित किया है, जिसमें से 75% निर्वासन के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है।"[169] लाखों गरीब अफगानों के जबरन निर्वासन से अफगानिस्तान में विनाशकारी मानवीय संकट और भी बढ़ सकता है, जहाँ लाखों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। यूएनएचसीआर और आईओएम ने कहा कि ये घटनाक्रम, जिनमें महिलाओं और लड़कियों को जबरन देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता हैं, उनके लिए 'गंभीर सुरक्षा जोखिम' पैदा करते हैं।[170] अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने बेदखली की निंदा की है तथा निर्णय को पलटने की मांग की है।

अफगान शरणार्थियों के आगमन और निर्वासन दोनों के मुद्दे ने पाकिस्तान और ईरान के साथ संबंधों को खराब करने में योगदान दिया। शरणार्थियों का मुद्दा ईरान और पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंधों में एक कांटा बना रहेगा। मध्य एशियाई पड़ोसियों के मामले में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन

देशों ने तालिबान शासन से भाग रहे आम अफगानों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं, फिर भी उन्होंने कुछ अफगान शरणार्थियों को शरण दी, और कथित तौर पर, वे अभी भी अनिश्चितता में रह रहे हैं और उन्हें लगातार अफगानिस्तान वापस भेज दिए जाने का खतरा बना हुआ है।

167 "Pakistan, Iran Jointly Deport Over 500,000 Afghan Nationals." VOA, November 21, 2023. Available at: https://www.voanews.com/a/pakistan-iran-jointly-deport-over-500-000-afghan-nationals-/7364231.html

168 "Taliban: Pakistan, Iran expelled over 400,000 Afghan refugees so far in 2024." Voice of America, June 10, 2024. Available at: https://www.voanews.com/a/taliban-pakistan-iran-expelled-over-400-000-afghan-refugees-so-far-in-2024/7650196.html

169 Ibid

170 Afghans return to Taliban rule as Pakistan moves to expel 1.7 million, Reuters, Op.cit.

अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से, इस्लामिक स्टेट के क्षेत्रीय सहयोगी आईएसकेपी से उत्पन्न ख़तरा बढ़ गया है।

मीडिया सूत्रों ने बताया कि 2021 और 2022 के बीच लगभग 200 अफगानों को मध्य एशियाई देशों से निष्कासित कर दिया गया।[171] यद्यपि इस समय शरणार्थी मुद्दा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यह दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव पैदा कर सकता है।

आईएसकेपी से बढ़ता ख़तरा

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से, इस्लामिक स्टेट के क्षेत्रीय सहयोगी आईएसकेपी से उत्पन्न खतरा बढ़ गया है।[172] इस्लामिक स्टेट ने 2015 में इस अफगान सहयोगी संगठन के गठन की घोषणा की थी और आईएसकेपी को 2016 में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। आईएसकेपी ने हाल के दिनों में कई देशों, जिनमें मार्च 2024 में रूस भी शामिल है, में साजिश रची है और अभियान चलाए हैं।

फरवरी 2020 में अमेरिका-तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से, आईएसकेपी ने शहरी क्षेत्रों और विदेशी संपत्तियों को तेजी से

निशाना बनाया है, जैसा कि 2020 में कई हमलों से स्पष्ट है, जिसमें काबुल गुरुद्वारा हमला, काबुल में मेडिसिन सेन्स फ्रंटियर्स क्लिनिक पर हमला, जलालाबाद जेल हमला, काबुल विश्वविद्यालय हमला और काबुल स्कूल बम विस्फोट शामिल हैं।

171 "Afghan Refugees Face Uncertainty in Central Asia". The Diplomat, September 8, 2022

172 "The Growing Threat of the Islamic State in Afghanistan and South Asia."USIP, June 2023. Available at: https://www.usip.org/publications/2023/06/growing-threat-islamic-state-afghanistan-and-south-asia.

आईएसकेपी क्षेत्र की सभी सरकारों के साथ-साथ उनके साथ संबद्ध प्रमुख शक्तियों का भी विरोध करता है।[173] आईएसकेपी शुरू में पूर्वी अफगानिस्तान में केंद्रित था, जो पाकिस्तान के उस क्षेत्र की सीमा पर था जिसे पहले संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। आईएसकेपी का मुख्य क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान बना हुआ है; हालांकि, इस्लामिक स्टेट के मुख्य संगठन ने ईरान में भी कई हमले किए हैं, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में छोटे पैमाने पर हमले किए हैं और भारत में हिंसा को बढ़ावा दिया है।[174] कथित तौर पर, उसने अपनी रणनीति को क्षेत्र पर नियंत्रण करने से बदलकर शहरी युद्ध करने की ओर मोड़ दिया है। अपनी अंतरराष्ट्रीय सदस्यता और महत्वाकांक्षाओं के साथ, आईएसकेपी तालिबान शासन, पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशियाई राज्यों और भारत सहित क्षेत्र की सभी सरकारों के लिए खतरा है।[175] यूरोप में कई साजिशों के पीछे इसका हाथ रहा है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने के साथ-साथ अमेरिका के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, चीन और रूस, दोनों पर हमला करने की क्षमता विकसित करना चाहता है।[176]

फरवरी 2020 में यूएस-तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से, आईएसकेपी ने शहरी क्षेत्रों और विदेशी संपत्तियों को तेजी से निशाना बनाया है, जैसा कि 2020 में कई हमलों से स्पष्ट हुआ है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ काबुल गुरुद्वारा हमला, काबुल में मेडिसिन सेन्स फ्रंटियर्स क्लिनिक पर हमला, जलालाबाद जेल

हमला, काबुल विश्वविद्यालय हमला और काबुल स्कूल बम विस्फोट आदि शामिल हैं। आईएसकेपी ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सैन्य वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट भी

173 The Islamic State in Khorasan Province: Exploiting a Counter Terrorism Gap". CSIS, April 11, 2024. Available at: https://www.csis.org/analysis/islamic-state-khorasan-province-exploiting-counterterrorism-gap

174 "Terrorist Groups in Afghanistan". Congressional Research Service, April 2, 2024. Available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10604

175 "The Islamic State in Khorasan Province: Exploiting a Counter Terrorism Gap". CSIS, April 11, 2024. Available at: https://www.csis.org/analysis/islamic-state-khorasan-province-exploiting-counterterrorism-gap

176 Ibid

दिलचस्प बात यह है कि अंतर-जिहादी प्रतिद्वंद्विता
केवल भौतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है,
बल्कि साइबर क्षेत्र तक भी फैल गई है।
विशेष रूप से, आईएसकेपी ने तालिबान की वैधता को चुनौती देने और खुद को जिहादी विचारधारा
के संरक्षक के रूप में पेश करने के लिए
अपने प्रचार प्रयासों को तेज कर दिया है।

किया था जिसमें दर्जनों अमेरिकी सेवा सदस्य और सैकड़ों अफगान मारे गए और घायल हुए थे।

पिछले कुछ वर्षों में, कई हमलों में अफगानिस्तान के शिया अल्पसंख्यक हजारा समुदाय को निशाना बनाया गया। तालिबान की वापसी से पहले भी, हजारा बहुल क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों और प्रसूति वार्डों को आईएसकेपी द्वारा निशाना बनाया गया था। पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक समारोहों, स्कूलों, मस्जिदों और अस्पताल के वार्डों में हज़ारा लोगों पर हमले होते रहे हैं। यूएनएएमए के अनुसार, तालिबान के कब्जे के बाद से पहले 21 महीनों में लगभग 345 हजारा लोग मारे गए या घायल हुए। 1 अगस्त से 7 नवंबर 2023 के बीच, संयुक्त राष्ट्र ने आईएसकेपी द्वारा नागरिकों, विशेष रूप से शियाओं को निशाना बनाकर किए गए आठ हमलों को दर्ज किया।[177]

अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद, तालिबान शासन ने शुरू में इस समूह का मुकाबला करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, जिसमें सलाफी समुदायों पर कार्रवाई भी शामिल थी।[178] तालिबान

को आईएसकेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने में कुछ सफलता मिली है, जिसमें एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो काबुल हवाई अड्डे पर समूह के हमलों के लिए जिम्मेदार था, की हत्या भी शामिल है । बहरहाल, तालिबान के सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद आईएसकेपी की गतिविधियां अपने चरम पर पहुँच गईं और असामान्य रूप से लंबे समय तक उनकी गति और अधिक बनी रही।

177 "Civilian Casualties since Taliban Takeover: New UNAMA report shows Sharp drop." UNAMA, June 27, 2023. Available at: https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/ civilian-casualties-since-the-taleban-takeover-new-unama-report-shows-sharp-drop-but-some-communities-still-under-threat/#:~:text=Since%20the%20takeover%2C%20UNAMA%20has,)%20or%20wounded%20(250).

178 The Islamic State in Khorasan Province: Exploiting a Counter Terrorism Gap". CSIS, April 11, 2024. Available at: https://www.csis.org/analysis/islamic-state-khorasan-province-exploiting-counterterrorism-gap

2021 के मध्य से, समूह ने तालिबान के खिलाफ हमले बढ़ा दिए, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए (मार्च और जून 2023 में प्रांतीय गवर्नरों सहित), साथ ही बाहरी रूप से उन्मुख संचालन, जिसमें उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के खिलाफ सीमा पार रॉकेट हमले, काबुल में रूसी और पाकिस्तानी दूतावासों पर हमले और चीनी नागरिकों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले काबुल होटल पर हमला शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान आईएसकेपी को अपने शासन के लिए मुख्य खतरा मानता है और उसने इसके खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि अंतर-जिहादी प्रतिद्वंद्विता केवल भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साइबर क्षेत्र तक भी फैल गई है। विशेष रूप से आईएसकेपी ने तालिबान की वैधता को चुनौती देने और खुद को जिहादी विचारधारा के संरक्षक के रूप में पेश करने के लिए अपने प्रचार प्रयासों को तेज कर दिया है। आईएसकेपी ने मास्को कॉन्सर्ट हमले के बाद पश्तो भाषा में 30 पृष्ठ का एक बयान जारी किया, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की आलोचना की गई तथा उसका मजाक उड़ाया गया।[179] तालिबान ने हमले के कुछ ही घंटों बाद इसकी निंदा की और इसे आतंकवादी हमला तथा मानवीय मानदंडों का उल्लंघन बताया। वर्तमान में, इस्लामिक स्टेट एक सैन्य और महत्वपूर्ण मीडिया इकाई के रूप में कार्य करता है। अपनी ~~स्थापना के बाद से, आईएसकेपी~~ ने अपनी डिजिटल उपस्थिति को

प्राथमिकता दी है, और यह किसी केंद्रीकृत वेबसाइट पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने संदेश के प्रचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करता है। तालिबान विरोधी मजबूत रुख के साथ, आईएसकेपी का ध्यान वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर फैला हुआ है, तथा इसका लक्ष्य मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य एशिया के दर्शक हैं। प्रचार सामग्री कई भाषाओं में तैयार की जाती है, जिनमें उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, रूसी, फारसी, ताजिक, उज्बेक, हिंदी, तमिल, मलयालम, अरबी, रूसी, दारी और बंगाली शामिल हैं।[180] व्यापक डिजिटल

179 "Islamic State-Khorasan Criticizes Taliban in Statement Praising Russia Attackers." Voice of America, March 25, 2024. Available at: https://www.voanews.com/a/islamic-state-khorasan-criticizes-taliban-in-statement-praising-russia-attackers-/7542235.html

180 Ibid

प्रचार पहल ने 30,000 से अधिक व्यक्तियों को अपने परिवारों को त्यागने और जिहाद के मार्ग पर चलने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया है।[181]

एक हालिया अध्ययन[182] में आतंकवाद विरोधी तीन कमियों की पहचान की गई है, जिनका फायदा क्षेत्र में आईएसकेपी द्वारा उठाया जा रहा है; सबसे पहले, आतंकवादी समूह को सरकारों की इस प्रवृत्ति से लाभ मिलता है जब वे समूह को अपने प्रतिद्वंद्वियों के उत्पाद के रूप में गलत निदान करती हैं। दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव में, आईएसकेपी का मुकाबला करने का कार्य काफी हद तक अफगान तालिबान पर आ गया है, जिससे दूसरी कमी उत्पन्न होती है। मार्च 2024 में, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि तालिबान ने [आईएसकेपी] का मुकाबला करने में प्रगति की है, लेकिन उन्हें [आईएसकेपी] की गुप्त शहरी कोशिकाओं को खत्म करने और आसान लक्ष्यों पर हमलों को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।[183] अंतिम यह कि, सामरिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने तथा यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में छिड़े प्रमुख संघर्षों के परिणामस्वरूप आतंकवाद-रोधी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रुचि कम हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में बड़े हमले करने की आईएसकेपी की क्षमता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई है, लेकिन

इस समूह के बारे में चिंता की बात यह है कि यह अफगानिस्तान से बाहर भी हमले करने की क्षमता रखता है।

181 Awasthi, Soumya. "Digital Battleground: ISKP Vs. Taliban" ORF, April 8, 2024. Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/digital-battleground-iskp-vs-taliban#:~:text=Notably%2C%20the%20Islamic%20State%20of,the%20custodian%20of%20jihadist%20ideology.

पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में बड़े हमले करने की आईएसकेपी की क्षमता का पर्याप्त प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस समूह के बारे में चिंता की बात यह है कि यह अफगानिस्तान से बाहर भी हमले करने की क्षमता रखता है।

182 The Islamic State in Khorasan Province: Exploiting a Counter Terrorism Gap". CSIS, April 11, 2024. Available at: https://www.csis.org/analysis/islamic-state-khorasan-province-exploiting-counterterrorism-gap

183 "Terrorism Groups in Afghanistan". Congressional Research Service, April 2, 2024. Available at: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10604

अफ़गानिस्तान के दक्षिण में, जहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मिलते हैं, तथाकथित गोल्डन क्रीसेंट है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के गोल्डन ट्राइंगल के साथ एशिया का सबसे कुख्यात ड्रग तस्करी केंद्र है।

ईरान में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट और मॉस्को में सिटी हॉल पर हमले ने यह प्रदर्शित कर दिया कि यह समूह अपनी बाह्य परिचालन क्षमता का विस्तार कर रहा है। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से, आईएसकेपी ने अपने प्रचार उत्पादन और आतंकवादी अभियानों में क्षेत्रीयकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण की रणनीति अपनाई है। इस सिद्धांत के उत्तरार्द्ध ने शाखा को अफगानिस्तान में विदेशी राजनयिक सुविधाओं और नागरिकों के विरुद्ध लक्ष्य बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, साथ ही इसकी बाह्य परिचालन गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। इसके अभियान का क्षेत्रीयकरण घटक मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य एशिया पर केंद्रित रहा है, लेकिन इसकी शाखा अपना विस्तार भी कर रही है तथा ईरान, भारत, तुर्की और यूरोप पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।[184] आईएसकेपी वर्तमान में इस्लामिक स्टेट के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सहयोगियों में से एक है। भविष्य में भी इसके

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्र में साजिश रचने की क्षमता बरकरार रहने की संभावना है। इसकी अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं इसे इसके आकार से कहीं अधिक तथा अफगानिस्तान से भी काफी आगे तक खतरा बनाती हैं।

अफ़गानिस्तान से नशीले पदार्थों की तस्करी

अफ़गानिस्तान में नशीले पदार्थों के उत्पादन का अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इनमें से कई देश वैश्विक मादक पदार्थों के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो अगस्त 2021 से फल-फूल रहा है।

184 "Islamic State Khorasan's Westward Network Expansion into Iran, Turkey, and Europe." The Diplomat, April 30, 2024. Available at: https://thediplomat.com/2024/04/islamic-state-khorasans-westward-network-expansion-into-iran-turkey-and-europe/

तालिबान के अंतरिम प्रशासन द्वारा अफ़ीम की खेती और पूरे अफ़गानिस्तान में सभी प्रकार के नशीले पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बावजूद, देश से नशीले पदार्थों की तस्करी पड़ोसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

अफगानिस्तान के दक्षिण में, जहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मिलते हैं, तथाकथित गोल्डन क्रीसेंट है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के गोल्डन ट्राइंगल के साथ एशिया का सबसे कुख्यात ड्रग तस्करी केंद्र है।[185] पाकिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान से एशियाई, अफ्रीकी, तथा पश्चिमी और मध्य यूरोपीय बाजारों तक मादक पदार्थों की तस्करी के दक्षिणी मार्ग पर हैं, जबकि ईरान, बाल्कन मार्ग का भी हिस्सा है जो तुर्कीए से होकर गुजरता है। दोनों ही देश अफगानिस्तान के साथ लंबी सीमाएं और गहरे सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं तथा लोगों और वस्तुओं की वैध और अवैध सीमा पार आवाजाही बहुत अधिक होती है, तथा सीमावर्ती समुदाय अपनी आजीविका के लिए तस्करी पर निर्भर रहते हैं। मध्य एशिया भी अफगानिस्तान से रूस और यूरोप तक नशीली दवाओं के लिए एक प्रमुख मार्ग बना हुआ है। ताजिकिस्तान इस उत्तरी मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण देश है और मध्य एशिया में नशीली दवाओं के खिलाफ प्रमुख चुनौतियों को दर्शाता है।

सिंथेटिक नशीले पदार्थ उत्पादन में वृद्धि पड़ोसियों और सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए

गंभीर चिंता का विषय होगी, और यह मुद्दा आने वाले दिनों में तालिबान शासन और अफगानिस्तान के पड़ोसियों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है।

185 "Impact of Afghanistan's Drug trade on its neighbours". SOC ACE Research Paper, November 2023. Available at: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/11/SOCACE-RP25-AfganDrugTradeImpact-20Nov23.pdf

तालिबान के अंतरिम प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान में अफीम की खेती और सभी प्रकार के नशीले पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बावजूद, देश से मादक पदार्थों की तस्करी पड़ोसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। जनवरी 2024 में, कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने घोषणा की कि 4,472 टन नशीले पदार्थ नष्ट कर दिए गए, उत्पादन और तस्करी में शामिल 8,282 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 13,904 हेक्टेयर अफीम की फसल को साफ कर दिया गया।[186] संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल 2022 में तालिबान के सर्वोच्च नेता द्वारा अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने के बाद से अफगानिस्तान में अफीम की खेती में भारी कमी की पुष्टि की है।[187] हालांकि, पोस्ता अफगानिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसलिए, सवाल यह है कि अंतरिम शासन अन्य फसलों की ओर बढ़ने के लिए क्या सहायता प्रदान करेगा और, इससे संबंधित, अगर ढहती हुई अफगान अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो अगले खेती के मौसमों में प्रतिबंध कितना टिकाऊ होगा। इसके अलावा, अफीम की खेती पर प्रतिबंध के कारण पैदा हुए शून्य के कारण सिंथेटिक दवा बाजार में उछाल आया है, विशेष रूप से अफगानिस्तान में मेथाम्फेटामाइन उत्पादन में। मेथाम्फेटामाइन की जब्ती की संख्या में वृद्धि, साथ ही मेथाम्फेटामाइन के निर्माणकर्ता देश की रिपोर्ट से पता चलता है कि सिंथेटिक ड्रग्स

15 अगस्त, 2024 को अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन के तीन साल पूरे हो जाएँगे। पिछले कुछ सालों में, दूसरे क्षेत्रों में संघर्ष के नए क्षेत्रों के उभरने से अफ़गानिस्तान वैश्विक ध्यान के हाशिये पर चला गया है।

186 "Taliban Maintain Poppy Crackdown, US Fears Farmers' Return to Cultivation."VoA, January 3, 2024. Available at: https://www.voanews.com/a/taliban-maintain-poppy-crackdown-us-fears-farmers-return-to-cultivation/7425417.html

187 Ibid

जबकि एक समावेशी सरकार बनाने की माँग जारी रही, क्षेत्र के देशों (साथ ही वैश्विक शक्तियों) ने शासन के साथ संचार ढांचा स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है।

चिंता का विषय बन रहे हैं।[188] सिंथेटिक दवा उत्पादन में वृद्धि पड़ोसियों और सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय होगी, और यह मुद्दा आने वाले दिनों में तालिबान शासन और अफगानिस्तान के पड़ोसियों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

15 अगस्त 2024 को अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तीन वर्ष पूरे हो जाएँगे। पिछले वर्षों में, अन्य क्षेत्रों में संघर्ष के नए क्षेत्रों के उद्भव ने अफगानिस्तान को वैश्विक फोकस के हाशिये पर धकेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामान्य तौर पर यूरोप और पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान में अपनी

भागीदारी को मानवीय सहायता तक ही सीमित रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से आतंकवादरोधी निगरानी की भूमिका पर वापस कदम रख

188 "Afghanistan's Opium Survey" UNODC, August 2023. Available at: https://www.drugsandalcohol.ie/39871/1/Afghanistan_opium_survey_2023.pdf

अखुंदजादा को केंद्रीय व्यक्ति बनाकर सत्ता को मजबूत करने में सक्षम हो गया है। देश में वर्तमान में एक अंतरिम मंत्रिमंडल द्वारा शासन किया जा रहा है जो न तो समावेशी है और न ही प्रतिनिधित्वपूर्ण है।

Sapru
House
Paper

तालिबान ने 2021 में सत्ता संभालने के बाद कठोर उपायों के तहत महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में प्रवेश से रोक दिया है और लड़कियों को छठी कक्षा से आगे स्कूल जाने से रोक दिया है। हालांकि, शुरुआत में अधिक उदार शासन का वादा किया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने आलोचना की थी।

दिया है। जबकि एक समावेशी सरकार बनाने की माँग जारी रही, क्षेत्र के देशों (साथ ही वैश्विक शक्तियों) ने शासन के साथ संचार ढांचा स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। कूटनीतिक रूप से, मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करने के तालिबान के प्रयासों के बावजूद, उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान कई दूतावासों ने या तो वहाँ अपने मिशन बनाए रखे हैं, जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और कुछ कार्सिनोजेन्स (सीएआरएस) शामिल हैं, या फिर वे तब से अफगानिस्तान लौट आए हैं, जिनमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, यह संख्या तालिबान के सत्ता में पहले कार्यकाल के दौरान बनाए गए मिशनों की संख्या से काफी अधिक है। है। हालाँकि, किसी ने भी तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।

आंतरिक रूप से, तालिबान अमीर अल-मुमिनिन, हिबतुल्लाह

अखुंदजादा को केंद्रीय व्यक्ति बनाकर सत्ता को मजबूत करने में सक्षम हो गया है। देश में वर्तमान में एक अंतरिम मंत्रिमंडल द्वारा शासन किया

वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय समर्थन और वित्तपोषण की कमी के कारण तालिबान विरोधी प्रतिरोध एक निराशाजनक संभावना का सामना कर रहा है। वर्तमान में, आईएसकेपी तालिबान शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सशस्त्र विपक्ष के रूप में उभरा है, जिसने तालिबान और उनके पदाधिकारियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक शिया समुदाय और नागरिकों को निशाना बनाते हुए कई प्रांतों में अपने अभियान का विस्तार किया है।

क्षेत्रीय स्तर पर, अफगानिस्तान के पड़ोसी इस तथ्य के आदी हो गए हैं कि तालिबान अमेरिका के बाद के अफगानिस्तान की निर्विवाद वास्तविकता का हिस्सा है और इसलिए, वे दीर्घकालिक शत्रुता को दरकिनार कर उनके साथ सह-अस्तित्व के लिए कूटनीतिक प्रयास बढ़ा रहे हैं।

जा रहा है जो न तो समावेशी है और न ही प्रतिनिधित्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद, तालिबान नेता एक समावेशी सरकारी संरचना बनाने या विभिन्न अफगान समूहों के साथ सार्थक बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अंतर-जातीय संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित जातीय समूहों को बढ़ते हाशिए, पूर्वाग्रह और जबरन बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। अफगान जनता पर थोपी गई नीतियों के परिणामस्वरूप मानव अधिकारों का निरंतर, व्यवस्थित हनन हुआ है, जिसमें शिक्षा, काम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने और संगठन बनाने का अधिकार शामिल है। तालिबान ने 2021 में सत्ता संभालने के बाद कठोर उपायों के तहत महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में प्रवेश से रोक दिया है और लड़कियों को छठी कक्षा से आगे स्कूल जाने से रोक दिया है। हालांकि, शुरुआत में अधिक उदार शासन का वादा किया गया था, अंतरराष्ट्रीय

समुदाय ने इसकी आलोचना की है। देश भर में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, विशेषकर अफगान गणराज्य के अंतिम वर्षों की तुलना में। जून 2024 में यूएनएएमए की मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि दो तालिबान विरोधी प्रतिरोध समूहों, अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा और अफगानिस्तान स्वतंत्रता मोर्चा ने हाल के महीनों में राजधानी और उत्तरी प्रांतों में सत्यापित हमले किए हैं, सशस्त्र विपक्ष ने अगस्त 2021 में सत्ता हासिल करने के बाद से क्षेत्रीय नियंत्रण पर तालिबान की पकड़ के लिए 'कोई महत्वपूर्ण चुनौती पेश नहीं की है'।[189]

वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और वित्तपोषण की कमी के कारण तालिबान विरोधी प्रतिरोध की संभावना धूमिल हो रही है। वर्तमान में, आईएसकेपी तालिबान शासन के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सशस्त्र विपक्ष के रूप में उभरा है, जिसने तालिबान और उनके पदाधिकारियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक शिया समुदाय और नागरिकों को निशाना बनाते हुए कई प्रांतों में अपने अभियानों का विस्तार किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय जिहादी समूहों के अत्यधिक जमावड़े पर चिंता जताई है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को अस्थिर करना चाहते हैं, और अफगान तालिबान से इन समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि तालिबान का इन विदेशी आतंकवादी समूहों पर किस प्रकार का प्रभाव है, लेकिन अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान अपने पूर्व सहयोगियों के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने के लिए उत्सुक नहीं है, विशेषकर ऐसे समय में जब उनकी उपस्थिति का उपयोग पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार में लाभ के रूप में किया जा सकता है।

क्षेत्रीय स्तर पर, अफगानिस्तान के पड़ोसी इस तथ्य के आदी हो गए हैं कि तालिबान अमेरिका के बाद के अफगानिस्तान की निर्विवाद वास्तविकता का हिस्सा है और इसलिए, वे दीर्घकालिक शत्रुता को दरकिनार कर उनके साथ सह-अस्तित्व के लिए कूटनीतिक प्रयास बढ़ा रहे हैं। तालिबान शासन की संदिग्ध घरेलू नीतियों के बावजूद, यह आम धारणा है कि यह शासन निकट भविष्य में बना रहेगा। परिणामस्वरूप, पड़ोसी

देशों ने समूह के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंध बढ़ा दिए हैं, हालांकि किसी भी देश ने तालिबान प्रशासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। इस क्षेत्र में, डूरंड रेखा और पाकिस्तान द्वारा उस पर लगाई गई बाड़ तथा अफगान क्षेत्र के अंदर टीटीपी की

189 "UN documents surge in anti-Taliban attacks in Afghanistan". VoA, June 21, 2024. Available at: https://www.voanews.com/a/un-documents-surge-in-anti-taliban-attacks-in-afghanistan/7665035.html

वर्तमान में, कई पड़ोसी देशों की काबुल में राजनयिक उपस्थिति है, और कुछ ने अपनी राजधानियों में तालिबान राजनयिकों का स्वागत किया है। यह रेखांकित करता है कि इस तरह के प्रतिनिधित्व निहित या स्पष्ट मान्यता के बराबर नहीं हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ सह-अस्तित्व के प्रबंधन के लिए एक तकनीकी पूर्वापेक्षा है।

उपस्थिति के कारण पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव के संकेत मिल रहे हैं, जहाँ उन्हें शरण देने के संदेह में स्थानीय आबादी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा तोपखाने और हवाई हमले किए गए हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमलों को बेअसर किया जा सके। पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों के निष्कासन से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। ईरान, जिसने क्षेत्र से अमेरिका और नाटो की वापसी के बाद अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे का सावधानीपूर्वक स्वागत किया था, अफगान शरणार्थियों की आमद, जल आपूर्ति और खुरासान में आईएसआईएस के प्रसार को लेकर चिंतित है। मध्य एशियाई देशों की नीति अब तक उनके व्यावहारिक हितों के सावधानीपूर्वक आकलन तथा शासन को मान्यता देने से बचने पर आधारित रही है। यद्यपि तालिबान शासन के प्रारंभिक दिनों में मध्य एशियाई देशों (CARs) के साथ तालिबान शासन के जुड़ाव में कुछ गिरावट देखी गई, लेकिन अंततः व्यावहारिकता

और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की ही जीत हुई। फिर भी, कोश तेपा नहर परियोजना (जिस पर तालिबान काम कर रहा है) और अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा, अफगान- मध्य एशियाई देशों के संबंधों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रतीत होता है। अफगानिस्तान के साथ चीन का जुड़ाव दो प्राथमिक चिंताओं से प्रेरित है, विदेशी सैन्य समूहों का खतरा और आर्थिक हितों की सुरक्षा। बीजिंग पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका को भी दूर रखने का इच्छुक है। अंततः, काबुल के पतन के बाद अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति अफगानिस्तान के लोगों पर ध्यान

'इस्लामिक अमीरात' को मान्यता न दिए जाने तथा समावेशी सरकार की स्थापना की सांकेतिक मांग के मुद्दों को छोड़कर, क्षेत्र के अधिकांश देशों ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने तथा आर्थिक और निवेश के अवसरों की तलाश के लिए तालिबान के साथ व्यापार करने की कोशिश की है; इस प्रक्रिया में, उन्होंने अपनी घरेलू नीतियों से मुंह मोड़ लिया है तथा महिलाओं और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन जारी रखा है।

केन्द्रित करते हुए वृद्धिशील सहभागिता के रूप में विकसित हुई है, तथा साथ ही तालिबान पर अधिक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए दबाव डाला गया है। वर्तमान में, कई पड़ोसी देशों की काबुल में राजनयिक उपस्थिति है, और कुछ ने अपनी राजधानियों में तालिबान राजनयिकों का स्वागत किया है। इससे यह रेखांकित होता है कि इस तरह के प्रतिनिधित्व में निहित या स्पष्ट मान्यता नहीं है, बल्कि यह अफगानिस्तान के साथ सह-अस्तित्व के प्रबंधन के लिए एक तकनीकी पूर्वापेक्षा है।[190] ये कार्य-स्तरीय संबंध, पूरी संभावना है कि निकट भविष्य में और अधिक बढ़ेंगे, लेकिन इनकी प्रकृति अधिक अनियमित होने की संभावना है।

जहाँ तक पश्चिमी देशों का प्रश्न है, वे मुख्य रूप से इस बात से चिंतित हैं कि अफगानिस्तान शत्रुतापूर्ण समूहों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बन सकता है, उन्हें डर है कि जिहादी संगठन पश्चिम के खिलाफ हमले करने के लिए आधार के रूप में इस देश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा चिंताओं के

अतिरिक्त, मानक मुद्दे भी हैं, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति तालिबान के व्यवहार के संबंध में, जिसके कारण कई सरकारें काबुल में नए अधिकारियों से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रख रही

190 "The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy with Afghanistan". International Crisis Group, Available at: The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy with Afghanistan | Crisis Group

एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान,
भले ही वह एक सत्तावादी शासन के
अधीन हो, क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा और
आर्थिक हितों के लिए लाभ पहुंचा
सकता है, लेकिन जैसा कि कहावत है,
'शहद मीठा होता है,
लेकिन मधुमक्खी डंक मारती है'।

उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि, 'इस्लामिक अमीरात' को मान्यता न देने और समावेशी सरकार की स्थापना की सांकेतिक मांग के मुद्दों को छोड़कर, क्षेत्र के अधिकांश देशों ने अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और आर्थिक और निवेश के अवसरों की तलाश करने के लिए तालिबान के साथ व्यापार करने की कोशिश की है; इस प्रक्रिया में, उन्होंने अपनी घरेलू नीतियों से दूर रहने का विकल्प चुना है और महिलाओं और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन जारी रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे तालिबान का हौसला बढ़ गया है, जो अपनी नीतियों पर कायम रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का जोखिम उठाने को तैयार है। एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान, भले ही वह एक सत्तावादी शासन के अधीन हो, क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन जैसा कि कहावत है, 'शहद मीठा होता है, लेकिन मधुमक्खी डंक मारती है'। आंतरिक सुरक्षा स्थिति में सुधार की दिशा में कुछ प्रगति के बावजूद, अफगानिस्तान अभी भी दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई देशों के लिए सुरक्षा खतरों का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। इसके अलावा, अफगानिस्तान अभी तक व्यापार करने के लिए एक बेहतर स्थान नहीं बन पाया है तथा निकट भविष्य में भी निवेश के लिए एक जटिल गंतव्य बना रहने की संभावना है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है, अफगानिस्तान का किसी भी भू-राजनीतिक या भू-आर्थिक ढांचे में एकीकरण एक दूरगामी लक्ष्य है।

लेखिका के बारे में

डॉ. अन्वेषा घोष वर्तमान में भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) नई दिल्ली में रिसर्च फेलो हैं। आईसीडब्ल्यूए अपनी भूमिका से पहले, उन्होंने जर्मनी के एरफर्ट विश्वविद्याल विली ब्रांट स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में व्याख्याता के रूप कार्य किया। डॉ. घोष ने जर्मनी के एरफ़र्ट विश्वविद्यालय से शांति और संघर्ष अध्ययन में डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कोलकाता में विदेश नीति अध्ययन संस्थान से एमफिल किया है और कलकत्ता विश्वविद्यालय रोम विश्वविद्यालय, ला सैपिएंज़ा से क्रमशः इतिहास और विकास अध्ययन में दोहरी मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र अफगानिस्तान है, साथ ही प्रवास, प्रवासी, की विदेश नीति और सहायता कूटनीति में भी उनकी शोध रुचि डॉ. घोष 'आइडेंटिटी एंड मर्जिनेलिटी इन इंडिया:सेटलमेंट एक्सपीरियंस ऑफ़ अफगान माइग्रेंट्स (रूटलेज: लंदन और न्यूयॉर्क, 2020) की लेखिका हैं।

SAPRU HOUSE PAPER

Indian Council
of World Affairs

Sapru House, Barakhamba Road, New Delhi 110 001, India
Tel. : +91-11-23317246, Fax: +91-11-23320638

www.icwa.in